Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 66
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.0
शनिवार, 14 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 त्र्यंबक-नाशिक कुंभ मेला विश्व के लिए आकर्षण ... 4 भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी ... 7 महिला क्रिकेट में 'नारी शक्ति' की क्रांति...

संक्षिप्त न्यूज

महुआ मोइत्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित 'सवाल के बदले नकद' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लोकपाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी देने की अनुमति दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस मामले में लोकपाल की याचिका पर महुआ मोइत्रा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और भारतीय जनता पार्टी के सांसद तथा शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का दिसंबर 2025 का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर 2025 को लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को कथित 'सवाल के बदले नकद' मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुच्छेद 89 में कहा था कि लोकपाल अधिनियम की धारा 20 के तहत स्वीकृति देने के संबंध में लोकपाल एक महीने के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करें।

सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकपाल अधिनियम की धारा 20 से संबंधित शक्तियों और प्रक्रियाओं पर उठे प्रश्नों से जुड़ी कई याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 89 पर रोक लगा दी है।

क्या है 'सवाल के बदले नकद' मामला

यह मामला उस आरोप से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने एक कारोबारी से नकद और उपहार लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछे थे।

असम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला

बोले- झूठे वादों की है दुकान, समुदायों के बीच पैदा किया विभाजन

गुवाहटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव वाले असम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर विभिन्न समुदायों में फूट डालने का आरोप लगाया और उसे झूठे वादों की दुकान करार दिया। गुवाहाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोकराझार में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बोडोलैंड की कई पीढ़ियों को झूठे सपनों में उलझाए रखा।

मोदी ने कहा कि जब आपने कांग्रेस को देश और असम दोनों से सत्ता से बेदखल कर भाजपा-एनडीए को सत्ता सौंपी, तो हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास शुरू किए। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न समुदायों में फूट डाली, जबकि भाजपा ने स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता हुआ था। पहली बार इस समझौते ने सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस झूठे वादों की दुकान है–और हर झूठे वादे के साथ, यह चार 'बड़े झूठ' बोनस उपहार के रूप में देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का उन वादों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए

की दो इंजन वाली सरकार असम की विरासत के संरक्षण और राज्य के तीव्र विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने पिछले कुछ दशकों में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया है; इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

आज, बोडोलैंड शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है। आज, असम शांति और प्रगति का एक नया अध्याय लिख रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बोडो समुदाय द्वारा अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित देखकर उन्हें गर्व होता है। उन्होंने कहा कि आपका प्रेम मेरे ऊपर एक ऋण के समान है, और मेरा उद्देश्य हमेशा से आपकी सेवा करके और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करके इस ऋण को चुकाना रहा है। कुछ सप्ताह पहले, मुझे गुवाहाटी में समृद्ध बोडो संस्कृति को देखने का अवसर मिला। आज इस क्षेत्र के विकास के लिए 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और आधारशिला रखी गई है। कोकराझार और पूरे क्षेत्र ने बीते दशकों में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ खोया भी है। हमने वो कठिन समय देखा है जब इन पहाड़ियों में बमों और तोपों की आवाज गूंजती थी। लेकिन आज ये तस्वीर बदल रही है। आज बोडोलैंड शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए विभिन्न समुदायों में फूट डालती थी, जबकि भाजपा ने शांति के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि 2020 के समझौते के तहत किए गए सभी वादे निरंतर प्रयासों से एक-एक करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बोडोलैंड के लिए 1,500 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज उपलब्ध कराया गया है। आज कोकराझार में एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वे सभी माताएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं जिनके बेटे घर लौट आए हैं और अब अपने परिवारों के साथ शांतिपूर्वक और खुशी से रह रहे हैं।

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी का मास्टरस्ट्रोक, 5 नए विकास बोर्ड बनाने का ऐलान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को राज्य के हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए पांच नए सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये बोर्ड उनकी अनूठी भाषाओं और परंपराओं की रक्षा करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सुनिश्चित करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार जल्द ही मुंडा (अनुसूचित जनजाति), कोरा (अनुसूचित जनजाति), डोम (अनुसूचित जनजाति), कुंभकार (अन्य पिछड़ा वर्ग) और सदगोपे (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदायों के लिए पांच नए सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डों का गठन करने जा रही है। ये समुदाय बंगाल की जीवंत संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई देती हूं।

उन्होंने आगे कहा कि इन बोर्डों का उद्देश्य पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना और समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। 'ये बोर्ड उनकी अनूठी भाषाओं और परंपराओं की रक्षा करते हुए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सुनिश्चित करेंगे। वे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और आगे सामाजिक-आर्थिक विकास लाएंगे। 2013 से हमने अपने कमजोर समुदायों के लिए ऐसे कई बोर्ड स्थापित किए हैं, जो उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हैं। एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि मां, माटी, मानुष के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अर्थ है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि कोई भी समुदाय पीछे न छूटे। हमारा लक्ष्य सरल हैः समावेशी प्रगति और

अटूट समर्थन के माध्यम से हर चेहरे पर मुस्कान लाना। जय बांग्ला।

यह 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगी, जो पिछले चुनावों में 77 सीटें जीतने के बाद इस बार भी जीत हासिल करना चाहेगी। यह कदम राष्ट्रपति मुर्मू की हाल ही में पश्चिम बंगाल यात्रा को लेकर हुए राजनीतिक विवाद के बाद उठाया गया है।

महाराष्ट्र में सभी वाहनों के लिए एक नियमः राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने अब पैसेंजर लेकर चलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-रिक्शा) और ई-बाइक के लिए परमिट लेना जरूरी कर दिया है। यह फैसला राज्य में नियमों को एक जैसा बनाने के लिए लिया गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को दी। इससे पहले, इलेक्ट्रिक ऑटो को अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब, जैसे-जैसे इन वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सरकार ने फैसला किया है कि सभी ई-रिक्शा और ई-बाइक को परमिट लेना होगा।

क्या है नए नियम, समझिए

राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के तहत अब इन वाहनों की नंबर प्लेट हरी पृष्ठभूमि और पीले अक्षरों वाली होगी। अब परंपरागत ऑटो, टैक्सी और इलेक्ट्रिक रिक्शा सभी पर एक जैसे नियम लागू होंगे। मंत्री सरनाईक ने बताया कि कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन कम होगा।

मामले में राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से सभी वाहनों में अनुशासन आएगा, नियमों का पालन होगा और यात्रियों को सुरक्षित सेवा मिलेगी। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि महाराष्ट्र परिवहन विभाग अब सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

एलपीजी संकट पर विपक्ष का हल्लाबोल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले सप्ताह के दौरान विपक्ष ने देश में कथित एलपीजी कमी के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। इस दौरान विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी उठाई।

शुक्रवार को सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए नोटिस सौंपे। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों की कथित कमी को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

संसद की कार्यवाही 16 मार्च तक स्थगित

बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला सप्ताह समाप्त होने के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 16 मार्च तक स्थगित कर दी गई है।

इस दौरान राज्यसभा में 18 निजी विधेयक पेश किए गए, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों के योगदान से संबंधित प्रावधान वाला विधेयक भी शामिल है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया।

लोकसभा ने अनुपूरक मांगों को दी मंजूरी

लोकसभा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को मंजूरी दे दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वैश्विक आर्थिक झटकों से निपटने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का आर्थिक स्थिरीकरण कोष बनाने की घोषणा की है। यह कोष पश्चिम एशिया में जारी संकट जैसी परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा।

सदन में हल्का-फुल्का पल

सदन में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर 'रावण' को अपना नाम बदलकर चंद्रशेखर 'विदुर' रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महाभारत के विदुर अत्यंत सम्मानित और विद्वान व्यक्तित्व थे और जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय बिजनौर में बिताया था।

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने बताया कि भारत के महापंजीयक कार्यालय ने बिहार सरकार से गंगोता समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव के संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा है। बिहार सरकार ने 4 नवंबर 2019 को इस संबंध में एक नृजातीय रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव भेजा था।

ईरान संकट के बीच भारत में रसोई गैस की 'पैनिक बुकिंग', रोजाना 20 लाख सिलेंडर की अतिरिक्त मांग

नई दिल्ली। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान संकट के बीच भारत में रसोई गैस की पैनिक बुकिंग तेजी से बढ़ गई है। लोगों द्वारा घबराहट में अतिरिक्त सिलेंडर बुक कराने के कारण देश में दैनिक एलपीजी बुकिंग 55 लाख से बढ़कर लगभग 75 लाख सिलेंडर प्रतिदिन तक पहुंच गई है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि युद्ध से पहले देश में रोजाना औसतन लगभग 55 लाख गैस सिलेंडर बुक होते थे। लेकिन हाल के दिनों में यह संख्या बढ़कर 75 लाख से अधिक हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वृद्धि वास्तविक कमी के कारण नहीं बल्कि घबराहट में की जा रही अतिरिक्त बुकिंग की वजह से है।

सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से सिलेंडर बुक न करें।

घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया

सरकार ने रसोई गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए घरेलू उत्पादन में लगभग

30 प्रतिशत तक वृद्धि की है। फिलहाल देश में उत्पादित गैस का पूरा हिस्सा घरेलू उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए।

आयात पर निर्भरता

भारत अपनी रसोई गैस की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। पहले देश की लगभग 60 प्रतिशत जरूरत आयात से पूरी होती थी। इसमें से लगभग 90 प्रतिशत आपूर्ति फारस की खाड़ी से होकर गुजरने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती रही है।

हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग पर दबाव बढ़ गया है। यह संकरा जलमार्ग खाड़ी क्षेत्र को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के तेल व गैस परिवहन का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। युद्ध के बाद कुछ टैंकरों को निशाना बनाए जाने की खबरों से अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है।

सरकार की तैयारी

स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं

गैस की उपलब्धता और वितरण की निगरानी के लिए विशेष समिति गठित की है

जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक आपूर्ति मार्गों पर भी विचार किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर भी फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि भारत लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है और देश में उपलब्ध आपूर्ति दैनिक जरूरत से अधिक बताई जा रही है।

इस बीच ईरान ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि उसने भारतीय झंडे वाले जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मध्य पूर्व में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार का दावा है कि भारत में रसोई गैस और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

तमिलनाडु चुनाव की तैयारी तेज, 16 मार्च को एम. के. स्टालिन की अध्यक्षता में बैठक

चेन्नई। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (डीएमके) ने अपनी रणनीति तेज कर दी है।

पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन 16 मार्च को जिला सचिवों के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी के महासचिव दुरईमुरुगन द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह बैठक सोमवार, 16 मार्च 2026 को सुबह 10:30 बजे चेन्नई स्थित अन्ना अरिवलयम के कलाइग्नार अरंगम सभागार में आयोजित की जाएगी। इसमें सभी जिला सचिवों और सांसदों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और जिला स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने की योजना पर

चर्चा की जाएगी। साथ ही चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति भी तय की जाएगी।

तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और चुनाव वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में होने की संभावना है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार को तेज कर रहे हैं और गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

इस बीच डीएमके के साथ समझौते के बाद मरुमलार्ची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम आगामी विधानसभा चुनाव में चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 11 मार्च को डीएमके प्रमुख एम. के. स्टालिन और एमडीएमके महासचिव वाइको के बीच बैठक हुई थी, जिसमें सीट बंटवारे पर सहमति बनी। इसके अनुसार धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के तहत एमडीएमके राज्य की चार विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

त्रिपुरा के राज्यपाल ने निवेश पर दिया जोर, विधानसभा में बोले- चुनौतियों को अवसरों में बदलें

अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेना रेड्डी ने शुक्रवार को कृषि, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनौतियों को अवसरों में बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया।

विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पुनर्जीवित त्रिपुरा की परिकल्पना नगरों के विकास, त्रिपुरेश्वरी मंदिर में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हैं।

डेस्टिनेशन त्रिपुरा के बारे में दी जानकारी

उन्होंने कहा, 'सरकार ने 2025 में 'डेस्टिनेशन त्रिपुरा' नामक एक व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें 120 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया और शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और आईटी क्षेत्रों में लगभग 3,800 करोड़ रुपये के 87 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।' रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे, निवेश और नवाचार पर विचारों के लिए 60 से अधिक अनिवासी भारतीयों को शामिल करते हुए, वर्चुअल रूप से पहला प्रवासी त्रिपुरवासी शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया।

कनेक्टिविटी पर कही यह बात

उन्होंने कहा, 'अटूट संकल्प के साथ, हम चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करेंगे, कृषि, उद्योगों और डिजिटल सशक्तिकरण में समावेशी विकास को बढ़ावा देंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य विकास का एक उज्ज्वल प्रतीक बने।' कनेक्टिविटी में हुए सुधारों पर राज्यपाल ने कहा कि रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण सब्रूम तक पूरा हो चुका है, जो रेल अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए खोवाई जिले के मुंगियाकामी से अगरतला तक राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के खंड को चार लेन का बनाने की एक व्यापक योजना तैयार की गई है।

एलपीजी संकट की खबरों पर एच. डी. देवेगौड़ा का बड़ा बयान, कहा- घबराने की कोई जरूरत नहीं

नई दिल्ली। एलपीजी की कथित कमी को लेकर देश में बढ़ रही चर्चाओं के बीच पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव के कारण आपूर्ति पर थोड़ा दबाव जरूर है, लेकिन सरकार स्थिति पर पूरी तरह नजर रखे हुए है।

राज्यसभा सांसद देवेगौड़ा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर कुछ असर पड़ा है। उन्होंने स्वीकार किया कि एलपीजी की थोड़ी बहुत कमी महसूस की जा रही है, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है और सरकार लगातार हालात की निगरानी कर रही है।

उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। देवेगौड़ा ने कहा कि सरकार ने स्थिति को लेकर पूरी स्पष्टता दिखाई है, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे को सरकार की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल

कर रहा है, चाहे उसमें सच्चाई हो या नहीं।

इस बीच शिवसेना के सांसद मिलिंद देवरा ने भी लोगों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से गैस खरीदने की क्षमता है और जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार कुछ लोग देश में बेवजह दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा कि केंद्र सरकार संसद को पहले ही आश्वस्त कर चुकी है कि स्थिति नियंत्रण में है। सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय और आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी संसाधनों की निगरानी हो और जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के. सुधाकर ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को एलपीजी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अतिक्रमण विभाग द्वारा ऐरोली क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त अभियान

दिव्यांश

मुंबई। नवी मुंबई महानगरपालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित लोगों ने नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इसके चलते अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नवी मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त आयुक्त (2) डॉ. राहुल गेठे और उप आयुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलास गायकवाड के मार्गदर्शन में अतिक्रमण विभाग द्वारा ऐरोली क्षेत्र में निष्कासन की कार्रवाई की गई।

नवी मुंबई महानगरपालिका के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जी विभाग, ऐरोली कार्यालय के अंतर्गत एसएस-2 / बी-229, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई में श्री बबन बाबू पवार, गुफरान खान (ठेकेदार) और ओमकार निर्गुडे (आर्किटेक्ट) द्वारा तथा एसएस-2 / बी-230, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई में श्री प्रेमानंद प्रजापति, गुफरान खान (ठेकेदार) और ओमकार निर्गुडे (आर्किटेक्ट) द्वारा महानगरपालिका की कोई भी अनुमति लिए बिना अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। श्री बबन बाबू पवार, गुफरान खान (ठेकेदार) और ओमकार निर्गुडे (आर्किटेक्ट), एसएस-2 / बी-229, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई तथा श्री प्रेमानंद प्रजापति, गुफरान खान (ठेकेदार) और ओमकार निर्गुडे (आर्किटेक्ट), एसएस-2 / बी-230, सेक्टर-02, ऐरोली, नवी मुंबई के अवैध निर्माण के संबंध में जी विभाग कार्यालय द्वारा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन एवं नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 54 के अंतर्गत नोटिस जारी की गई थी। संबंधित लोगों को स्वयं ही अवैध निर्माण हटाना आवश्यक था, लेकिन उन्होंने निर्माण कार्य जारी रखा। इसके कारण विभाग द्वारा दिनांक 02.02.2026 को आंशिक निष्कासन की कार्रवाई की गई थी।

हालांकि आज दिनांक 13.03.2026 को पुनः उक्त स्थान पर निर्माण कार्य जारी होने की जानकारी मिलने पर ऐरोली विभाग की सहायक आयुक्त एवं विभाग अधिकारी श्रीमती साधना पाटील के नियंत्रण में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया और अवैध निर्माण को आंशिक रूप से हटाया गया।

इस अभियान में जी विभाग कार्यालय के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, 10 मजदूर, 2 ब्रेकर मशीन, 1 गैस कटर तथा अतिक्रमण विभाग के पुलिस बल को तैनात किया गया था।

पश्चिम रेलवे के बोरीवली एवं भायंदर स्टेशनों के बीच ब्लॉक तथा प्रभादेवी स्टेशन पर मेजर ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालन कार्यों को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए बोरीवली एवं भायंदर स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर जम्बो ब्लॉक तथा प्रभादेवी स्टेशन पर शनिवार/रविवार, 14/15 मार्च, 2026 की मध्यरात्रि में प्रभादेवी रोड ओवर ब्रिज (पुल) के गर्डर के डी-लॉन्चिंग कार्य हेतु सभी लाइनों पर मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोरीवली एवं भायंदर स्टेशनों के बीच 00:15 बजे से 03:45 बजे तक लिया ब्लॉक जाएगा, जबकि प्रभादेवी स्टेशन पर 01:30 बजे से 06:00 बजे तक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

बोरीवली-भायंदर ब्लॉक के दौरान फास्ट लाइन की सभी ट्रेनें विरार/वसई रोड और बोरीवली के बीच स्लो लाइन पर चलाई जाएंगी। प्रभादेवी स्टेशन पर ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी तथा कुछ सेवाओं को दादर और बांद्रा से शॉर्ट टर्मिनेट कर वहीं से रिटर्न किया जाएगा। ब्लॉक अवधि के दौरान चर्चगेट और प्रभादेवी स्टेशनों के बीच तथा माटुंगा रोड और माहिम स्टेशनों पर कोई उपनगरीय ट्रेन सेवा

परिचालित नहीं होगी।

इन ब्लॉकों के कारण कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को सूरत और विरार के बीच रेगुलेट किया जाएगा अथवा रिशेड्युल किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

13 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09184 वाराणसी-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को 2 घंटा रेगुलेट किया जाएगा।

14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस को 1 घंटा 45 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12928 एकता नगर-दादर एक्सप्रेस को 1 घंटा रेगुलेट किया जाएगा।

14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12902 अहमदाबाद-दादर एक्सप्रेस को 1 घंटा रेगुलेट किया जाएगा।

14 मार्च, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09052 भुसावल-दादर एक्सप्रेस को 45 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

15 मार्च, 2026 को मुंबई सेंट्रल 05:40 बजे यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एक्सप्रेस 06:10 बजे प्रस्थान करेगी, अर्थात यह ट्रेन 30 मिनट रिशेड्युल किया जाएगा।

रविवार, 15 मार्च, 2026 को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

पश्चिम रेलवे ने लगातार चौथे वर्ष 100 मिलियन टन माल लदान का आँकड़ा पार किया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 12 मार्च, 2026 को प्रारंभिक माल लदान में 100 मिलियन टन का महत्वपूर्ण आँकड़ा पार कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ ही पश्चिम रेलवे ने लगातार चौथे वर्ष 100 मिलियन टन माल लदान का आँकड़ा पार किया है, जो माल परिवहन के क्षेत्र में उसके सुदृढ़ और निरंतर प्रदर्शन तथा देश के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को सशक्त बनाने में पश्चिम रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कई वस्तुओं के लदान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कंटेनर लदान 33.66 मिलियन टन रहा, जिसमें 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। उर्वरक लदान 18.92 मिलियन टन रहा, जिसमें लगभग 22 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। खाद्यान्न लदान 1 मिलियन टन रहा, जिसमें 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि लौह एवं इस्पात का लदान 0.69

मिलियन टन रहा, जिसमें लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीमेंट लदान 14.53 मिलियन टन रहा, जिसमें 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य वस्तुओं का लदान भी मजबूत रहा और यह 15.94 मिलियन टन दर्ज किया गया, जिसमें लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अप्रैल 2025 से 12 मार्च 2026 की अवधि के दौरान वस्तुवार माल लदान में कोयला, उर्वरक, कंटेनर, पीओएल, सीमेंट, खाद्यान्न, लौह एवं इस्पात तथा अन्य वस्तुएँ शामिल हैं, जिससे कुल माल लदान 100.02 मिलियन टन तक पहुँच गया। वर्ष के दौरान पश्चिम रेलवे ने सनोसरा, भीमासर, वरतेज, वडोदरा मार्शलिंग यार्ड, कड़ी, गांधीधाम आदि विभिन्न स्थानों से औद्योगिक नमक, प्याज, ऑटोमोबाइल आदि जैसी वस्तुओं में माल परिवहन के नए स्रोत भी विकसित किए गए। इससे पश्चिम रेलवे के माल परिवहन पोर्टफोलियो को और अधिक मजबूती मिली है।

पश्चिम रेलवे नए माल परिवहन स्रोतों को आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप माल परिवहन सेवाएँ प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जा सकी है।

कलाबुरगी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ने सेवा के 2 वर्ष पूरे किए, 5.72 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर, 103.52% ऑक्यूपेंसी दर्ज

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कलाबुरगी-सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया टर्मिनल (एसएमवीटी) बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ने 12 मार्च 2026 को अपनी सफल सेवा के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि आधुनिक रेल संपर्क और यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस प्रतिष्ठित सेवा का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। इस ट्रेन को कर्नाटक की राजधानी और आईटी हब बेंगलुरु तथा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के कलाबुरगी के बीच तेज और विश्वस्तरीय रेल संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इस ट्रेन ने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र और राज्य की राजधानी के बीच तेज तथा आरामदायक यात्रा को काफी सुदृढ़ बनाया है। यात्रा समय में कमी आने से व्यवसायियों, अधिकारियों, छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को विशेष लाभ मिला है। पिछले दो वर्षों में इस सेवा ने बेंगलुरु तक आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत किया है। इससे आईटी हब बेंगलुरु और उत्तर कर्नाटक के बाजारों के बीच व्यापार को भी बढ़ावा मिला है, वहीं

मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु तेज यात्रा भी संभव हुई है।

यह ट्रेन कलाबुरगी, यादगीर और रायचूर जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करती है। साथ ही तीर्थ और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे मंत्रालयम और पुट्टपर्थी (श्री सत्य साई प्रशांति निलयम के माध्यम से) जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान हो गई है।

ट्रेन संख्या 22231/22232 कलाबुरगी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस 561 किलोमीटर की दूरी केवल 8 घंटे में तय करती है, जबकि मौजूदा सुपरफास्ट ट्रेनों को यह दूरी तय करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस प्रकार यात्रियों का लगभग 2 से 4 घंटे का समय बचता है। वर्तमान में यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन संचालित होती है और यादगीर, रायचूर, मंत्रालयम रोड, गुंटकलम, अनंतपुर, साई पी. निलयम तथा येलहंका स्टेशनों पर ठहराव करती है।

8 कोच वाले वंदे भारत ट्रेन सेट में कुल 452 सीटों की क्षमता है, जिसमें 400 चेयर कार (CC) और 52 एग्जीक्यूटिव चेयर कार (EC) सीटें शामिल हैं। इस ट्रेन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2026 तक इस ट्रेन से कुल 5,72,566 यात्रियों ने यात्रा की है तथा वर्ष 2026 में इसकी 103.52 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है।

कलाबुरगी-एसएमवीटी बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस का सफलतापूर्वक दो वर्ष पूरे होना भारतीय रेल की आधुनिकीकरण, यात्री सुविधा, गति, सुरक्षा और सतत परिवहन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सेवा क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय संपर्क को भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

संपत्ति कर अब सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश पर भी जमा किया जा सकेगा

नवी मुंबई महानगरपालिका की नागरिकों के लिए विशेष सुविधा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई महानगरपालिका के संपत्ति कर विभाग द्वारा शहर में संपत्ति कर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर जमा करने के लिए अब केवल 18 दिन शेष हैं। इसलिए महानगरपालिका के मुख्य कार्यालय तथा शहर के 8 विभागीय कार्यालयों के अंतर्गत सभी कर वसूली केंद्र अब 31 मार्च 2026 तक शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे।

मार्च महीने में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा, 21 मार्च को रमजान ईद, 26 मार्च को श्री राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती जैसे सार्वजनिक अवकाश हैं। इन दिनों भी कर वसूली केंद्र नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। इससे नौकरीपेशा वर्ग और आम नागरिकों को छुट्टी के दिन भी कर जमा करने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कार्यदिवसों में सभी कर वसूली केंद्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। नवी मुंबई शहर के संपत्ति धारकों को आठों विभागीय कार्यालयों के कर वसूली केंद्रों पर जाकर सीधे कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही घर बैठे कर भुगतान के लिए कई ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

नागरिक व्हाट्सऐप चैटबॉट (8291920504), 'माय एनएमएमसी - माय नवी मुंबई' मोबाइल ऐप, महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट www.nmmc.gov.in, करदाताओं को दिए गए क्यूआर कोड स्कैन तथा विभिन्न यूपीआई अनुप्रयोगों के माध्यम से कर भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे डिजिटल भुगतान विकल्प भी उपलब्ध हैं।

नागरिकों की सुविधा के लिए संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान तंत्र भी उपलब्ध है। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट www.nmmc.gov.in व्हाट्सऐप चैटबॉट 8291920504 या कर वसूली केंद्र पर जाकर अपना संपत्ति कर जमा करें।

अभय योजना का लाभ उठाने का अंतिम अवसर; विलंब शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट

नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा संचालित अभय योजना का लाभ उठाने के लिए अब सीमित समय शेष है। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2026 तक बकाया संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने पर विलंब शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसलिए बकाया करधारकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है और उनसे तुरंत इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है।

नागरिकों की सुविधा के लिए शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी कर वसूली केंद्र खुले रखे गए हैं। गुड़ी पड़वा, रमजान ईद, श्री राम नवमी और महावीर जयंती के दिन भी कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने नागरिकों से अपील की है कि वे अभय योजना का लाभ उठाकर समय पर संपत्ति कर जमा करें और नवी मुंबई महानगरपालिका को सहयोग प्रदान करें।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र देश में शीर्ष पर - मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई। विश्व आर्थिक मंच, दावोस में हुए समझौतों के माध्यम से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) आ रहा है और वर्ष 2026 में 31 लाख करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह जानकारी मंत्री डॉ. उदय सामंत ने विधानसभा में नियम 293 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव के उत्तर में दी। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र लगातार तीन वर्षों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है।

मंत्री डॉ. सामंत ने कहा कि दावोस यात्रा के दौरान हुए समझौतों से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इस वर्ष किए गए समझौते केवल एमआईडीसी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उद्योग विभाग, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के माध्यम से भी बड़े निवेश समझौते किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग के माध्यम से 15 लाख 15 हजार करोड़ रुपये, एमएमआरडीए के माध्यम से 15 लाख 10 हजार करोड़ रुपये तथा एमएसआरडीसी के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के समझौते किए गए हैं। अन्य राज्यों में जहां अनुबंधों के क्रियान्वयन की दर 35 से 40 प्रतिशत है, वहीं महाराष्ट्र में वर्ष 2022 से यह दर 75 से 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

मुंबई में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति

मुंबई में आधारभूत संरचना के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका की सावधि जमा राशि सुरक्षित है और विकास कार्यों के लिए धन का उचित उपयोग किया जा रहा है। शहर में 1,048 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिनकी कुल लंबाई 278.83 किलोमीटर है। पहले चरण का लगभग 54 प्रतिशत और दूसरे चरण का 56 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

मीठी नदी परियोजना की जांच

मीठी नदी परियोजना के संबंध में उन्होंने बताया कि पहले इस कार्य में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके कारण जांच शुरू की गई है। जांच में लगभग 65 करोड़ रुपये की अनियमितता सामने आई है और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 380 करोड़ रुपये के टेंडर को रद्द कर नए टेंडर आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है।

एमआईडीसी क्षेत्र की झुग्गियों के पुनर्वास के लिए नई नीति

मंत्री डॉ. सामंत ने बताया कि राज्य सरकार एमआईडीसी भूमि पर स्थित झुग्गियों के पुनर्वास के लिए अलग नीति लाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक नीति और रत्न एवं आभूषण नीति की तर्ज पर एमआईडीसी क्षेत्र की झुग्गियों के लिए एसआरए नीति लाने की योजना है और इस संबंध में अगले दो महीनों में निर्णय लिया जाएगा।

इस नीति के माध्यम से एमआईडीसी भूमि पर वर्षों से रहने वाले परिवारों के पुनर्वास और उन्हें आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

मंत्री डॉ. उदय सामंत ने यह भी कहा कि राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास लाने के लिए नए एमआईडीसी क्षेत्रों की स्थापना, निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।

मध्य रेल में यात्री संख्या बढ़ने के साथ आय में उल्लेखनीय वृद्धि

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के दौरान यात्री यातायात में वृद्धि के साथ मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। इस अवधि में यात्री तथा वाणिज्यिक आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

यात्री यातायात

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य रेल ने कुल 1503.50 मिलियन यात्रियों का परिवहन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में परिवहन किए गए 1476.61 मिलियन यात्रियों की तुलना में 1.82 प्रतिशत अधिक है।

इसमें शामिल हैं -

1314.91 मिलियन उपनगरीय यात्री (पिछले वर्ष 1300.32 मिलियन)

188.58 मिलियन मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और अन्य गैर-उपनगरीय यात्री (पिछले वर्ष 176.28 मिलियन)

फरवरी 2026 के दौरान मध्य रेल ने कुल 130.10 मिलियन यात्रियों का परिवहन किया, जिनमें 112.98 मिलियन उपनगरीय तथा 17.13 मिलियन गैर-उपनगरीय यात्री शामिल हैं। पिछले वर्ष इसी माह में 128.27 मिलियन यात्रियों का परिवहन किया गया था।

यात्री एवं वाणिज्यिक आय

वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के दौरान मध्य रेल ने कुल ?16055.10 करोड़ की यात्री एवं वाणिज्यिक आय अर्जित की। इसमें शामिल हैं -

यात्री आय - ?7,296.73 करोड़

माल परिवहन आय - ?7,487.45 करोड़

अन्य कोचिंग आय - ?703.41 करोड़

विविध आय - ?567.51 करोड़

अन्य कोचिंग आय में ?118.89 करोड़ गैर-किराया पहलों से तथा ?231.02 करोड़ पार्सल परिवहन से प्राप्त हुए।

फरवरी 2026 के दौरान आय

फरवरी 2026 में मध्य रेल ने कुल ?1613.87 करोड़ की यात्री एवं वाणिज्यिक आय दर्ज की। इसमें शामिल हैं -

735.35 करोड़ यात्री आय

746.16 करोड़ माल परिवहन आय

62.61 करोड़ अन्य कोचिंग आय

69.75 करोड़ विविध आय

अन्य कोचिंग आय में ?10.31 करोड़ गैर-किराया पहलों से तथा ?21.05 करोड़ पार्सल परिवहन से प्राप्त हुए।

गैर-किराया राजस्व पहल

फरवरी 2026 के दौरान ई-नीलामी के माध्यम से 36 वाणिज्यिक अनुबंध प्रदान किए गए, जिनसे ?1246.60 लाख का वार्षिक लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुआ।

मुंबई मंडल में कई महत्वपूर्ण विज्ञापन अनुबंध अंतिम रूप से दिए गए, जिनमें उपनगरीय ट्रेनों के डिब्बों के अंदर विज्ञापन, माथेरान-नेरल टॉय ट्रेन पर विज्ञापन, तथा कुर्ला और सानपाडा कार शेड में रखे गए रेकों के अंदर और बाहर विज्ञापन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त घाटकोपर आरओबी पर होर्डिंग के लिए भी एक प्रमुख विज्ञापन अनुबंध प्रदान किया गया।

ग्लो साइन बोर्ड के माध्यम से लोणावला, अंबरनाथ, मुंब्रा, वांगनी बदलापुर, टिटवाला, वशिंद और कल्याण स्टेशनों पर नौ अनुबंध प्रदान किए गए।

अन्य वाणिज्यिक सुविधाओं में लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हेल्थ कियोस्क, भायखला, कंजूर मार्ग और भांडुप स्टेशनों पर खुदरा दुकानें तथा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस और दादर स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधाएं शामिल हैं।

इसके अलावा हार्बर, ट्रांस-हार्बर और बीएसयू लाइनों पर उपनगरीय ट्रेनों में वेंडिंग सेवाओं के लिए अनुबंध दिए गए हैं। साथ ही मुंबई उपनगरीय नेटवर्क के लिए 'यात्री' मोबाइल अनुप्रयोग हेतु भी अनुबंध प्रदान किया गया है।

नागपुर मंडल में वंजरी नगर स्थित होर्डिंग स्थल के माध्यम से विज्ञापन अधिकार दिए गए हैं।

पश्चिम रेलवे

अल्ट्रा सोनिक परीक्षण हेतु ई-टेंडर आमंत्रित

पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल के वरिष्ठ मंडल अभियंता (दक्षिण) कार्यालय द्वारा ई-टेंडर संख्या ँएऊ/25-26/340 (दिनांक 10.03.2026) के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। **कार्य एवं स्थानः** चर्चगेट-विरार खंड में रेल/वेल्ड के अल्ट्रा सोनिक परीक्षण के लिए भारतीय रेलवे की मानक विशिष्टताओं के अनुसार परीक्षण कार्य किया जाएगा। यह परीक्षण आरडीएसओ द्वारा संशोधित वर्ष 2022 के प्रावधानों के अनुसार पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के चर्चगेट-विरार खंड में किया जाएगा। **कार्य की अनुमानित लागतः** 9,80,759.70 **धरोहर राशि (ईएमडी):** 19,600 **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः** 07.04.2026, दोपहर 3:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि व समयः** 07.04.2026, दोपहर 3:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की ई-निविदा वेबसाइट www.ireps.gov.in पर देखा जा सकता है। 1213

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

MAHATRANSCO
Maharashtra State Electricity Transmission Co. Ltd.

e-TENDER NOTICE

MSETCL invites online bids (e-Tender) from reputed and registered contractors on Mahatransco e-Tendering Website **https://srmetender.mahatransco.in/** for the following Tender specification.

RFX	Description	Esti. Cost
Tend-25/25-26 **RFX 7000038594 ...3rd call**	SITC, 22kV feeder for M/s. JTL plant at 220kV Kandalgaon S/stn under EHV (O&M) Circle, Panvel	**Rs. 35.14 Lakhs**

EMD 1% of estimated cost. **Tender Fee: Rs. 500/- + GST. Submission of bids from 12.03.2026 to 23.03.2026 up to 11:00 hrs, Opening date: 23.03.2026 @ 11:30 Hrs.** For further details visit our website

https://srmetender.mahatransco.in/

Contact Person : The Executive Engineer (Adm) Mob. No. 8412050202. E-mail ID **se7200@mahatransco.in**

Sd/-
SUPERINTENDING ENGINEER
EHV (O&M) CIRCLE, PANVEL

नाशिक सिंहस्थ कुंभ मेला शिखर समिति की बैठक संपन्न

त्र्यंबक-नाशिक कुंभ मेला विश्व के लिए आकर्षण बने - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

त्र्यंबक-नाशिक कुंभ मेले के लिए 22,181 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। वर्ष 2027 में त्र्यंबक-नाशिक में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। यहां आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ भारत और महाराष्ट्र की छवि लेकर जाएगा। इसलिए इसके सफल आयोजन के माध्यम से ऐसा कुंभ मेला आयोजित किया जाए जो पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए।

विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कुंभ मेला शिखर समिति की बैठक में त्र्यंबक-नाशिक सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए 22,181 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें पहले चरण में 5,140 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 17,041 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कुंभ मेले के लिए चल रहे या प्रस्तावित कार्यों में यदि कोई व्यक्ति दुर्भावना से बाधा डालता है या जानबूझकर देरी करने का प्रयास करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबळ, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, विधायक सीमा हिरे, देवयानी फरांदे, सरोज अहिरे, पंकज

भुजबळ, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बांकर, हीरामन खोसकर, राहुल ढिकले तथा नाशिक की महापौर हिमगौरी आहेर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कुंभ मेले से संबंधित विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। नाशिक रिंग रोड के कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करते हुए 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए। कुंभ मेले में स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए शौचालयों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि कुंभ मेले के अवसर पर नाशिक के आसपास के रेलवे स्टेशनों के आधारभूत ढांचे के विकास का कार्य रेलवे द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसमें निफाड रेलवे स्टेशन को भी शामिल करने के संबंध में रेलवे विभाग को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु शिरडी और शनि शिंगणापुर भी जाते हैं, इसलिए शिरडी-नाशिक मार्ग का कार्य भी किया जाए। श्रद्धालुओं को संचार में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मोबाइल संचार प्रणाली को मजबूत किया जाए और इसकी तैयारी अभी से की जाए।

द्वारका जंक्शन पर यातायात सुचारु करने के लिए चल रहे कार्यों के दौरान आसपास की आंतरिक सड़कों को भी समग्र रूप से विकसित किया जाए। नए घाटों के निर्माण के लिए किसानों को भूमि का उचित भुगतान किया जाए। साथ ही त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड और नाशिक की गोदावरी नदी का पानी कुंभ मेले के दौरान स्वच्छ रहे, इसके लिए संबंधित एजेंसियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

नाशिक के कालाराम मंदिर क्षेत्र में कार्य करते समय आसपास के यातायात को बाधित न होने देने के निर्देश दिए गए। राम काल पथ के कार्य में तेजी लाई जाए। शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत खराब पड़े सीसीटीवी की जांच कर नए सीसीटीवी लगाने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी देने के निर्देश भी दिए गए।

अमृत स्नान के दौरान शहर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों के परिसर में पार्किंग और पुलिस व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित विभागों से चर्चा कर निर्णय लेने को कहा गया। निवृत्तिनाथ मंदिर ट्रस्ट के कार्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुंभ मेले के अवसर पर नाशिक शहर और आसपास के 2 से 4 हजार युवाओं को आवश्यक कौशल का प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक के रूप में तैयार किया जाए। साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित कर एक सशक्त व्यावसायिक मॉडल विकसित किया जाए।

बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए 'डिजिटल कवच' आवश्यक - महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सुरक्षित और जिम्मेदार तकनीक उपयोग सुनिश्चित करके बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने हेतु 'डिजिटल कवच' तैयार करने की आवश्यकता है। यह बात महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कही।

डिजिटल युग की चुनौतियों, विशेषकर बाल सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा के लिए 'महा-संकल्प : सुरक्षा, शिक्षा और सतत डिजिटल भारत' शीर्षक से नेतृत्व संवाद का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चाइल्डफंड इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष नंदिनी आओडे, सचिव लक्ष्मण राउत, अवर सचिव वंदना जैन, चाइल्डफंड इंडिया के कार्यकारी निदेशक आनंद विश्वकर्मा, विभिन्न कॉरपोरेट संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, वकील, प्राध्यापक, फिल्म निर्माता तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपस्थित थे।

मंत्री अदिति तटकरे ने अपने संदेश में बताया कि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 करोड़ बच्चे हैं और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट, कृत्रिम

बुद्धिमत्ता और डिजिटल मंचों का बढ़ता उपयोग बच्चों के लिए शिक्षा और नवाचार के नए अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, हानिकारक सामग्री और गेमिंग की लत जैसी नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में इस संवाद से प्रभावी समाधान निकलने की उम्मीद है।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल संरक्षण के लिए बाल-अनुकूल मोबाइल वैन दस्ते शुरू किए हैं, जो सड़क पर रहने वाले और संवेदनशील बच्चों तक पहुंचकर उन्हें परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।

'वेब सेफ एंड वाइज' पहल के अंतर्गत महाराष्ट्र को पायलट राज्य बनाया गया है। इसके माध्यम से 12 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर धोखाधड़ी और जिम्मेदार डिजिटल उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इस पहल में विद्यार्थी, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पुलिस तथा समुदाय के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

मंत्री तटकरे ने यह भी बताया कि भविष्य में विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, अभिभावकों में जागरूकता फैलाने, तकनीकी कंपनियों द्वारा 'सेफ्टी बाय डिजाइन' सिद्धांत अपनाने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

साथ ही ऑनलाइन बाल उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए 1930 हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है, ताकि ऐसे मामलों में तुरंत सहायता और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

सभी शर्तें पूरी होने पर ही गुठेवारी प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी - मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। गुठेवारी नियमितीकरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करना आवश्यक है और केवल वही प्रस्ताव मंजूर किए जाते हैं जो संबंधित मानदंडों को पूरा करते हैं। यदि आवश्यक दस्तावेज और तकनीकी शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो संबंधित प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए गुठेवारी विकास को नियमित करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करना जरूरी है, ऐसा मंत्री डॉ. उदय सामंत ने विधान परिषद में कहा।

सदस्य योगेश टिलेकर ने नियम 97 के तहत हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान इस संबंध में सुझाव प्रस्तुत किया था। इस चर्चा में सदस्य प्रवीण दरेकर ने भी भाग लिया। मंत्री डॉ. उदय सामंत ने बताया कि राज्य सरकार ने 30 अप्रैल 2001 से पूरे महाराष्ट्र में गुठेवारी विकास नियमितीकरण अधिनियम लागू किया है। इसके अनुसार पुणे महानगरपालिका ने 12 फरवरी 2021 को शहर सुधार समिति के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर गुठेवारी विकास के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की।

अब तक इस संबंध में कुल 1133 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं 731 प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है और 327 प्रस्तावों पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। अस्वीकृत प्रस्तावों के पीछे कई कारण हैं, जिनमें गणना नक्शे की उपलब्धता न होना, अपेक्षा से अधिक अतिरिक्त निर्माण किया जाना, रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभाव तथा हवाई अड्डे के फनल जोन में निर्माण किया जाना शामिल है। इन कारणों से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जा सकी।

मंत्री सामंत ने स्पष्ट किया कि फनल जोन में स्थित घरों को आयकर में छूट देना, ऐसे घरों को अनुमति प्रदान करना और रक्षा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गुठेवारी नियमितीकरण के प्रति सकारात्मक है, लेकिन यदि सभी निर्माण बिना किसी शुल्क के नियमित कर दिए जाते हैं तो इससे महानगरपालिका के राजस्व में कमी आएगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का बोझ होगा कम - उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया गया है। छात्राओं को 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस में छूट तथा छात्रों को 50 प्रतिशत ट्यूशन फीस में छूट दी जा रही है। इस निर्णय के बावजूद यदि कोई महाविद्यालय विद्यार्थियों से फीस वसूलता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आज विधानसभा में कहा।

मंत्री पाटिल विधायक रईस शेख द्वारा लंबित फीस प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति वितरण में आ रही कठिनाइयों के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने बताया कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कई समय लेने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। छात्रवृत्ति आवेदन में मांगी जाने वाली जानकारी 138 से घटाकर 66 कर दी गई है तथा आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 17 से घटाकर 8 कर दी गई है। अब सीईटी के आँकड़ों का सीधे उपयोग किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को जाति प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज बार-बार जमा नहीं करने पड़ेंगे।

महाविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की पहली

किस्त जल्दी वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने वेतन से भी अधिक प्राथमिकता छात्रवृत्ति वितरण को देने के निर्देश दिए हैं, जिसे जून माह से लागू किया जाएगा।

मंत्री पाटिल ने बताया कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के लिए 'कमाओ और सीखो' जैसी नई योजना के माध्यम से लगभग 5 लाख विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपये अतिरिक्त मानधन देने की योजना बना रही है। हालांकि इस योजना की अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण, पुस्तकालय प्रबंधन या सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे। इसके लिए सरकार, महाविद्यालय और सामाजिक संस्थाएं मिलकर निधि जुटाएंगी।

इसके अलावा जीवन निर्वाह भत्ता योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरों की श्रेणी के अनुसार 10 महीनों के लिए छात्रावास भत्ता दिया जाता है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में प्रति माह 6000 रुपये (कुल 60000 रुपये), जिला स्तर पर 5100 रुपये तथा तहसील स्तर पर 4800 रुपये दिए जाते हैं।

मंत्री पाटिल ने यह भी बताया कि लंबित भुगतान समय पर करने के लिए कुछ वित्तीय संस्थानों (जैसे फेडरल बैंक) के साथ चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत सरकार ब्याज का भुगतान करेगी और ये संस्थाएं सीधे विद्यार्थियों या महाविद्यालयों की फीस का भुगतान करेंगी, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद यदि कोई महाविद्यालय विद्यार्थियों से अनुचित 'अन्य शुल्क' वसूलता है या प्रवेश प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र भरते समय होने वाली त्रुटियों से बचने के लिए राज्य में 40 सहायता केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को फॉर्म भरने और तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी।

इस प्रश्न पर हुई चर्चा में विधायक सुधीर मुनगंटीवार और कैलास पाटिल ने भी भाग लिया।

चेक पोस्ट बंद करने की दिशा में सरकार की कार्रवाई शुरू - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। चेक पोस्ट के संबंध में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों से प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया है। राज्य में चेक पोस्ट बंद करने के संबंध में सरकार सकारात्मक है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में दी।

इस विषय पर विधायक नाना पटोले ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया था।

परिवहन मंत्री सरनाईक ने बताया कि चेक पोस्ट रद्द करने के संबंध में केंद्र सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं। उसी के अनुसार राज्य सरकार ने भी राज्य में चेक पोस्ट बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि, चेक पोस्ट से संबंधित पहले किए गए समझौते की अवधि अभी बाकी होने के कारण इस मामले में कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में संबंधित कंपनी के साथ पत्राचार किया गया है और समझौते की शर्तों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट पर अनियमितताओं की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई है, इसलिए इस मामले की जांच की जा रही है। यदि जांच में ठेकेदार या संबंधित अधिकारी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री सरनाईक ने कहा कि इस विषय में कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली गई है और मौजूदा समझौते के प्रावधानों के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। राज्य में चेक पोस्ट बंद करने के संबंध में सरकार उचित कदम उठाएगी।

विधानसभा की कार्यवाही :

मछली पालन संस्थाओं में अनियमितताओं के प्रमाण मिलने पर होगी जांच - मंत्री नितेश राणे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य में मीठे पानी के मत्स्य पालन को बढ़ावा देते हुए यदि किसी संस्था के कार्य में कोई त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है और उसके संबंध में ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सरकार निश्चित रूप से जांच कराएगी। यह जानकारी मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने विधानसभा में दी।

विधायक प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नांदेड़ जिले के लोहा तालुका में कार्यरत जय मल्हार मच्छीमार संस्था, गावंडगांव, मल्हारी मार्तंड भुजलशायी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित, आंदगा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भुजलशायी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, मालेगांव तथा राजमाता अहिल्यादेवी भुजलशायी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, घोटका के कार्यों के संबंध में प्रश्न उठाए थे। मंत्री राणे इस पर उत्तर दे रहे थे।

मंत्री राणे ने बताया कि संबंधित संस्था वर्तमान में प्रतिवर्ष लगभग 120 टन मछली उत्पादन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में मीठे पानी के मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर किसी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। एक ओर जहां

उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर संस्थाओं को बंद करना सरकार के हित में नहीं है।

मंत्री राणे ने बताया कि शिकायतकर्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 120 (ए) के अंतर्गत इस मामले में अपील कर सकते हैं। मत्स्य विभाग मत्स्य पालन संस्थाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी करेगा।

राज्य के सभी विद्यालयों में मराठी भाषा अनिवार्य; नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई - स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन बोर्ड के विद्यालयों में मराठी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधानसभा में कहा।

मंत्री भुसे विधायक हारून खान द्वारा इस विषय पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने बताया कि 1 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन के विद्यालयों में मराठी भाषा विषय अनिवार्य किया गया है। कुछ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बोर्ड के पाठ्यक्रमों में मराठी को दूसरी भाषा या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में मराठी भाषा को हटाया नहीं जा सकता।

विधायक हारून खान द्वारा जिस विद्यालय के संबंध में शिकायत की गई है, उसका शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल निरीक्षण कराया जाएगा। यदि वहां मराठी भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है, तो विद्यालय को कानून की जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मंत्री भुसे ने कहा।

मंत्री भुसे ने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालयों में मराठी भाषा पढ़ाने का नियम केवल सरकारी विद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निजी, अनुदानित तथा विदेशी बोर्ड के सभी विद्यालयों पर भी लागू होता है। मराठी राज्य की राजभाषा है, इसलिए उसका संरक्षण करना और नई पीढ़ी को उसका शिक्षण देना आवश्यक है। इस विषय पर राज्य सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।

जिन विद्यालयों में मराठी भाषा नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें पहले समझाइश देकर नियम लागू कराया जाएगा। यदि कोई संस्था इस आदेश का पालन नहीं करती है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

इस विषय पर हुई चर्चा में विधायक अतुल भातखलकर और अमित देशमुख ने भी भाग लिया।

मोरदारी झील परियोजना के प्रति सरकार का सकारात्मक रुख - आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उइके

मुंबई। मोरदारी जलसंचय झील योजना से आदिवासी किसानों और स्थानीय नागरिकों को पेयजल तथा सिंचाई दोनों का लाभ मिलेगा, इसलिए आदिवासी विकास विभाग इस परियोजना को सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा पहले से शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं की लंबित वित्तीय देनदारियां कम होने के बाद मोरदारी जलसंचय झील योजना को प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक मंजूरी दी जाएगी, ऐसा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उइके ने कहा।

अहिल्यानगर जिले के अकोले में मोरदारी जलसंचय झील परियोजना के कार्य के दौरान नींव की खुदाई में तटबंध (डाइक) आने के कारण परियोजना की लागत बढ़ गई है और 2624.27 लाख रुपये का संशोधित बजट प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव लंबित होने के कारण विधायक डॉ. किरण लहामटे ने विधानसभा में प्रस्ताव के माध्यम से 125 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल के लिए तत्काल वित्तीय प्रावधान करने की मांग की थी।

इस पर उत्तर देते हुए आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उइके ने बताया कि इस जलसंचय टैंक योजना को वर्ष 2014 में जिला योजना समिति (डीपीडीसी) के माध्यम से जिला योजना योजना के अंतर्गत प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। संशोधित प्रशासनिक मंजूरी विभाग के पास समीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया गया है। इस योजना से 125 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा और वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

मंत्री डॉ. उइके ने बताया कि वर्तमान में आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से 19 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और उन पर बड़ी वित्तीय देनदारी है। जब तक इन संबंधित परियोजनाओं का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक नई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी देने में कठिनाई आ रही है।

वाकुर्डे उपसा सिंचाई योजना को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा - मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल

मुंबई। सातारा जिले की दक्षिण मांड घाटी के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिए लागू की जा रही वाकुर्डे उपसा सिंचाई योजना को जल्द ही सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। इससे बिजली खर्च में बचत होगी और सिंचाई प्रबंधन अधिक प्रभावी बनेगा। यह जानकारी जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने विधानसभा में दी। इस विषय पर विधायक अतुल भोसले ने एक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया था।

जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि सातारा जिले में दक्षिण मांड नदी घाटी का कुल क्षेत्र लगभग 6687 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से 1309 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सिंचाई का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कराड तालुका में दक्षिण मांड नदी घाटी का ऊंचा और पहाड़ी क्षेत्र सूखाग्रस्त होने के कारण इस क्षेत्र के लिए वाकुर्डे उपसा सिंचाई योजना लागू की जा रही है। इस योजना के माध्यम से 19 गांवों के लगभग 2200 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। जल दर महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है और इसमें बिजली, रखरखाव तथा संचालन खर्च को ध्यान में रखते हुए शुल्क लगाया जाता है। मंत्री विखे पाटिल ने बताया कि 15 मार्च 2024 के सरकारी निर्णय के अनुसार राज्य की सभी उच्च दाब और अति उच्च दाब उपसा सिंचाई योजनाओं को लगभग 1053 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़ने को मंजूरी दी गई है।

सम्पादकीय

'कुछ मीठा हो जाए' या 'कुछ बीमार हो जाए'? विज्ञापनों के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई

आहार का स्वाद बनाए रखने के लिए चीनी और नमक बहुत जरूरी है। दुनिया के मशहूर बावर्ची खास और महंगे व्यंजन पकाते हुए नमक की बारी आने पर कहते हैं- स्वादानुसार। नमक तो ज्यादा खाना वैसे भी संभव नहीं होता। मीठा कम खाने के बारे कोई नहीं कहता, इसलिए मीठा रुकने का नाम नहीं लेता। यह खूब खाया जाता है। इसके असर के बारे में जानते हुए भी लोग इससे बचना जरूरी नहीं समझते। हालांकि मोटापा, मधुमेह और दूसरे कारणों से जब शरीर परेशान होने लगता है, तब मीठा कम करना पड़ता है। हमारी जीवन शैली ही ऐसी है कि चीनी दुखी करने लगे, तब भी किसी न किसी बहाने मीठा खाना छूटता नहीं है। कितने ही लोग सुबह उठकर गोली खा लेते हैं और दिन में गुलाब जामुन पेश किए जाएं, तो उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते हैं। कोई खुशखबरी जिंदगी में इठलाती हुई प्रवेश कर जाए और जल्दी से कोई मिठाई न मिल सके, तो चीनी को ही मिठाई मान कर मुंह मीठा करा दिया जाता है। वैसे हर मिठाई में चीनी की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

लगभग हर प्रसाद में मिष्ठान खिलाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्यादा मीठा खाते रहना सेहत के लिए दिन पर दिन खतरनाक हुआ जा रहा है। खुशी मनाने और मनवाने के लिए मुंह मीठा करवाना हमारी ऐतिहासिक परंपरा है और परंपराओं से मुंह मोड़ना हमारे यहां सांस्कृतिक गुस्ताखी मानी जाती है। मीठा खाकर आराम से बैठने के कारण राष्ट्रीय सेहत बिगड़ रही है।

यह पढ़कर और जानकर कसैला अनुभव होता है कि हमारा देश दुनिया की मीठी राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। आशंका है कि वास्तविकता में यह हो भी चुका हो, क्योंकि सच अब बेचारा हो चुका है। पता नहीं वक्त के किस कोने में सिर झुकाए बैठा होगा। 'कुछ मीठा हो जाए' जैसे विज्ञापनों ने प्यार तो बहुत पाया, तभी सामान भी खूब बिकवाया, लेकिन जितना नुकसान मीठा खाते रहने वालों का हुआ, उतना मीठा खाने वाले नहीं समझते।

मिठास के पीछे दुनिया इतनी दीवानी है कि उत्सव और खुशियों की पारंपरिक मिठाई, यानी गुड़ को भी नहीं बख्शा गया। उसे ज्यादा मीठा, कुरकुरा और स्वाद बनाने के लिए उसमें चीनी मिलाना कब से हो रहा है। दर्जनों प्रसिद्ध ब्रांडों की गजक चीनी के सहारे बिक रही है। कितनी ही चीजों में असली चीनी की जगह जो नकली चीनी खिलाई जा रही है, वह असली चीनी से ज्यादा खतरनाक बताई जाती है। अच्छी सेहत के बारे में समझाने वाले उचित ही कहते हैं कि जब बीमारियां दस्तक देना शुरू कर रही हों तो भोजन में चीनी और नमक कम कर देना चाहिए। इस बारे में वाकई संजीदा विचार करना चाहिए और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कोई विज्ञापन प्रेरित करे या न करे, खुद ही अपने आप से कहा जाए कि मीठा ज्यादा नहीं, अब नमकीन भी कम हो जाए। यह दोनों शरीर में कम प्रवेश करेंगे, तो जिंदगी की असली सेहत सलामत रहेगी और तबीयत भी बार-बार खराब होने से बचा करेगी।

यह बिल्कुल सही कहा गया है कि डाक्टर के पास जाकर दवाई खाकर स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना नहीं है, बल्कि डाक्टर के पास न जाकर, स्वानुशासन अपनाकर स्वस्थ रहना ही वास्तव में स्वस्थ रहना है। यह बात दीगर है कि विषाणु, दुर्घटना, प्रदूषण और गरीबी के पड़ोस में तो कोई भी बीमार हो सकता है। खुशी मनाने के लिए 'कड़वा हो जाए' कहने का प्रचलन भी हमेशा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। मिठाई खाने से ज्यादा स्वाद तो लोग सोमरस पीने और पिलाने में लेते हैं।

यह पेय मिठाई खिलाने से कम रसीला नहीं माना जाता। यही माना जाता है कि खुशी की पार्टी तो तभी पूरी होती है, जब मदिरापान हो। एक बार मिली जिंदगी का पूरा लुत्फ लेने के लिए पीना पिलाना बढ़ रहा है। हमारे देश को इस तरह के स्वाद रस की खपत में दुनिया भर में काफी बढ़त मिली है। खुशी के अवसरों पर बच्चों, युवाओं और महिलाओं से बच बचाकर, 'आज शाम को पार्टी हो जाए' भी खुलकर कहा जा रहा है। अक्सर देखने में आया है कि चीनी और नमक से खबरदार करने वाले भी इस संदर्भ में कड़वे बोल नहीं कहते। जबकि इस तरह की पार्टी के बहाने शुरू हुई आदत का सिरा आगे चल कर सेहत के खिलाफ किस तरह खड़ा हो जाता है, यह छिपा नहीं रहा है। खुशी तो हम शरीर, दिल और दिमाग से भी महसूस कर सकते हैं। उसमें कुछ मीठा खाना तो बाहरी कर्म है।

कोई ताजा फल खा लिया जाए, तो भी जिंदगी में खुशी और उत्साह उभर सकता है। बदलते जमाने के साथ 'आज कुछ खट्टा-मीठा हो जाए' कहा जाए और खाया भी जाए तो क्या हर्ज है? यह बिल्कुल नया और सेहतमंद अनुभव होगा। किसी को मीठा ज्यादा परेशान कर रहा है, तो 'अब सिर्फ खट्टा हो जाए' बोल कर सिर्फ खट्टा ही खाया और खिलाया जा सकता है।

डगमगाती दुनिया के बीच स्थिर भारत : मोदी कूटनीति की शक्ति

प्रोफ़ेसर डॉ दयानंद तिवारी
(सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्, साहित्यकार एवं सामाजिक चिंतक)

'संकट ही नेतृत्व की असली परीक्षा होता है।'

जब परिस्थितियाँ सामान्य होती हैं, तब शासन चलाना अपेक्षाकृत सरल होता है, किंतु जब पूरी दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक तनाव से जूझ रही हो, तब किसी राष्ट्र को समृद्ध , स्थिर और संतुलित बनाए रखना ही वास्तविक नेतृत्व की पहचान बन जाता है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य अत्यंत जटिल और चिंताजनक दिखाई देता है। दुनिया के अनेक क्षेत्रों में युद्ध, राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष ने अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की आशंका पैदा कर दी है। तेल और गैस के दामों में उतार-चढ़ाव, समुद्री व्यापार मार्गों में बाधा और बढ़ती महंगाई ने विश्व समुदाय के सामने गंभीर चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब विश्व के अनेक देश संकट से जूझ रहे हैं, तब भारत किस प्रकार संतुलन बनाए हुए है।

आज की वैश्विक व्यवस्था में ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर निर्भर है। यदि किसी कारण से तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव सीधे उद्योग, परिवहन और कृषि पर पड़ता है। यही कारण है कि जब भी मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर दिखाई देता है। भारत भी इससे पूरी तरह अछूता नहीं है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत तेल अन्य देशों से आयात के माध्यम से पूरा करता है।

फिर भी यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत आज अपेक्षाकृत स्थिर और संतुलित दिखाई दे रहा है। इसका प्रमुख कारण भारत की दूरदर्शी नीतियाँ और मजबूत नेतृत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिनके कारण भारत 40 देशों के बीच वैश्विक संकटों के बीच भी मजबूती से खड़ा है।

भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका संतुलन है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह किसी भी संघर्ष में अनावश्यक पक्षपात के बजाय संवाद और शांति के मार्ग का समर्थन करता है। यही कारण है कि आज भारत के संबंध अमेरिका, यूरोप, रूस, मध्य-पूर्व और एशिया के देशों सहित लगभग सभी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ सकारात्मक बने हुए हैं। आज विश्व राजनीति में भारत को एक विश्वसनीय, संतुलित और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

भारत की आर्थिक रणनीति भी उसकी स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहन और विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाने जैसे अनेक सुधार किए हैं। इन प्रयासों ने भारत की आर्थिक शक्ति को नई ऊर्जा प्रदान की है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

अंग्रेज़ी की प्रसिद्ध उक्ति है कि...

'In the middle of difficulty lies opportunity.'

अर्थात कठिनाइयों के बीच ही अवसर छिपे होते हैं। भारत ने भी वैश्विक संकटों के बीच अवसरों को पहचानकर अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत करने का प्रयास किया है।

ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने दूरदर्शिता दिखाई है। भारत ने अपने तेल आयात के स्रोतों का विस्तार किया है तथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंचों पर भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई है। जी-20 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को सामने रखा।

संस्कृत का यह श्लोक भारत की इसी सोच को व्यक्त करता है कि...

'अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्?'

अर्थात संकीर्ण सोच वाले लोग ही अपना-पराया करते हैं, जबकि उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार है।

आज जब विश्व के अनेक देश युद्ध, आर्थिक संकट और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, तब भारत का संतुलित और स्थिर रहना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह केवल संयोग नहीं बल्कि दूरदर्शी नीतियों, मजबूत नेतृत्व और भारत की सांस्कृतिक सोच का परिणाम है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान वैश्विक संकट के बीच भारत एक संतुलित, जिम्मेदार और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। यदि भारत इसी संतुलित दृष्टिकोण और विकास की नीति पर आगे बढ़ता रहा, तो निश्चय ही वह न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

मेरा मन कहता है कि कहूँ...
संकट की घड़ी में जो राष्ट्र संभलकर आगे बढ़ता है,
वही इतिहास के पन्नों में उज्ज्वल भविष्य गढ़ता है।
विश्व डगमगाए चाहे जितना, भारत अडिग खड़ा रहेगा,
संतुलन, साहस और संकल्प से नया युग रचेगा।
जय हिंद

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया के युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बार फिर अस्थिर कर दिया है। तेल और गैस की आपूर्ति से जुड़े समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ने लगा है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तेज हो गया है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर देश के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। भारत की आर्थिक गतिविधियां, उद्योग, परिवहन व्यवस्था और आम लोगों का दैनिक जीवन काफी हद तक पेट्रोलियम उत्पादों और गैस पर निर्भर करता है। इसलिए मध्य-पूर्व में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित करता है। इस परिस्थिति में भारत सरकार को न केवल ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि अफवाहों और बाजार में पैदा होने वाली अनिश्चितता पर भी नियंत्रण रखना होगा।

मध्य-पूर्व लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्रों में शामिल रहा है। खाड़ी क्षेत्र से दुनिया के अनेक देशों को कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष का सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक चिंता समुद्री मार्गों को लेकर है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले अधिकांश तेल टैंकर महत्त्वपूर्ण समुद्री रास्तों से होकर गुजरते हैं।

अगर युद्ध के कारण इन मार्गों पर अवरोध उत्पन्न होता है, तो तेल की आपूर्ति में गंभीर बाधा आ सकती है। साथ ही जहाजों की सुरक्षा, बीमा लागत और परिवहन खर्च भी बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव आखिर तेल की कीमतों पर दिखाई देता है। भारत की ऊर्जा संरचना को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी भी बड़े पैमाने पर आयातित तेल और गैस पर निर्भर है। भारत

कच्चे तेल की अपनी कुल जरूरत का लगभग अस्सी फीसद से अधिक आयात करता है।

इनमें से एक बड़ा हिस्सा मध्य-पूर्व के देशों से आता है। यही कारण है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ते ही भारत में ऊर्जा बाजार को लेकर चिंता बढ़ जाती है। अगर युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति बाधित होती है या कीमतों में तेज वृद्धि होती है तो इसका प्रभाव सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल पेट्रोल और डीजल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव होता है। परिवहन महंगा होने से वस्तुओं की ढुलाई की लागत बढ़ती है, जिससे बाजार में कई वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं।

कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है, क्योंकि खेती से जुड़े कई उपकरण और परिवहन व्यवस्थाएं पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित हैं। इसी तरह, उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे उत्पादों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। परिणामस्वरूप महंगाई बढ़ने की संभावना बनती है और आम लोगों की क्रय शक्ति पर असर पड़ता है। प्राकृतिक गैस की स्थिति भी भारत के लिए उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। देश के कई उर्वरक संयंत्र, बिजली उत्पादन इकाइयां और औद्योगिक इकाइयां गैस पर निर्भर हैं।

भारत अपनी गैस जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका बड़ा भाग भी मध्य-पूर्व से आता है। अगर युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है, तो उर्वरक और बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। इससे कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों पर दबाव बढ़ सकता है। ऊर्जा संकट का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है। ऊर्जा संसाधनों की कमी या कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से किसी भी देश की विकास गति प्रभावित हो सकती है।

भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता बेहद जरूरी है। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो इससे देश का आयात खर्च बढ़ने के साथ-साथ व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। इसका असर मुद्रा विनिमय दर और वित्तीय संतुलन पर भी पड़ेगा। इन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाए।

सबसे पहले सरकार को विभिन्न देशों से तेल और गैस की खरीद के विकल्पों को मजबूत करना होगा, ताकि किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का उपयोग भी संकट के समय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रणनीतिक तेल भंडार तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य आपात स्थिति में देश की ऊर्जा जरूरतों को कुछ समय तक पूरा करना है। हालांकि केवल भंडार बनाना ही पर्याप्त नहीं है।

सरकार को ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा। रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से ऊर्जा आयात बढ़ाने की दिशा में पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं। इस नीति को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी एक क्षेत्र में संकट उत्पन्न होने पर देश की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित न हो। ऊर्जा संकट की स्थिति में एक और महत्त्वपूर्ण पहलू समाज में फैलने वाली अफवाहें होती हैं। कई बार सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ऐसी खबरें फैल जाती हैं कि देश में ईंधन की कमी होने वाली है या पेट्रोल-डीजल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ने वाली हैं।

ऐसी अफवाहों के कारण लोग घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण करने लगते हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार और प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वे समय-समय पर स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी जनता तक पहुंचाते रहें। मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। ऊर्जा संकट जैसे संवेदनशील विषयों पर अतिरंजना या अपुष्ट जानकारी समाज में अनावश्यक भय और भ्रम पैदा कर सकती है।

दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो यह संकट भारत के लिए एक चेतावनी भी है कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाएं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के विकास से भविष्य में तेल और गैस पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी काफी संभावनाएं शेष हैं।

मध्य-पूर्व का वर्तमान संकट यह स्पष्ट संकेत देता है कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का प्रभाव पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत के लिए यह समय सतर्कता, संतुलन और दूरदर्शिता के साथ नीति बनाने का है। सरकार को ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बाजार में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। साथ ही अफवाहों और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए पारदर्शी सूचना प्रणाली और जिम्मेदार संवाद भी जरूरी है।

अगर भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में संयम के साथ कदम उठाता है, तो वह न केवल इस संभावित ऊर्जा संकट से सुरक्षित रह सकता है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी मजबूत आधार तैयार कर सकता है। ऐसी परिस्थितियां कठिन जरूर होती हैं, लेकिन सही नीति और दूरदर्शिता के माध्यम से इन्हें अवसर में भी बदला जा सकता है। यही समय है जब भारत को अपनी ऊर्जा नीति को और अधिक मजबूत, संतुलित और भविष्योन्मुखी बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाने होंगे।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, वैश्विक व्यापार चुनौतियां और भारत की रणनीति

अमेरिका में 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रम्प ने 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ट्रम्प के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पूरी दुनिया में, विशेष रूप आर्थिक क्षेत्र में भारी उथल पुथल दिखाई दी है। ट्रम्प ने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' - अमेरिका को पुनः महान बनायें - के नारे के साथ यह राष्ट्रपति चुनाव जीता था। अतः उन्होंने अमेरिका को एक बार पुनः विश्व के विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने विभिन्न देशों से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर टैरिफ लगाने का निर्णय लेते हुए, इस निर्णय को शीघ्र ही लागू भी कर दिया। उनका सोचना था कि उनके इस निर्णय से विभिन्न उत्पादों के निर्यातक अमेरिका में इन उत्पादों को निर्यात करने के प्रति निरुत्साहित होकर इन उत्पादों का उत्पादन अमेरिका में ही प्रारम्भ कर देंगे। इस कार्य को यदि धीमे धीमे एवं संरचित रूप से किया जाता तो सम्भव है कि पूरे विश्व में अफरा तफरी जैसा माहौल नहीं बनता। परंतु, ट्रम्प ने कुछ देशों (चीन, आदि) से विभिन्न वस्तुओं के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी एवं अन्य देशों को भी लगातार इस प्रकार की धमकी देना प्रारम्भ कर दिया।

ट्रम्प ने भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर भी 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया एवं 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ यह कहते हुए लगाया कि भारत, रूस से कच्चे तेल का आयात करता है एवं इसे प्रसंस्कृत करने के उपरांत यूरोपीय देशों को पेट्रोल एवं डीजल के रूप में निर्यात करता है। इस प्रक्रिया में ट्रम्प ने यह निष्कर्ष निकाला भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल को खरीदने से रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को बल मिलता है और भारत इस युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग कर रहा है। इस प्रकार, भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर दिनांक 27 अगस्त 2025 से 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया गया है। इससे भारत के पूंजी (शेयर) बाजार में हाहाकर मच गया एवं विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारत से अपने निवेश को निकाल रहे हैं।

ट्रम्प अमेरिका में होने वाले विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगाए गए टैरिफ पर ही नहीं रुके बल्कि अपनी साम्राज्यवादी सोच को पुनः लागू करने के उद्देश्य को भी स्पष्ट रूप से झलका दिया। प्रभुतासम्पन्न देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अमेरिका में लाया गया एवं उन पर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया। दरअसल, अमरीका की नजर वेनेजुएला के कच्चे तेल के अपार भंडार पर है। जिस पर अमेरिका अपना कब्जा स्थापित करते हुए इसके उपयोग पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। साथ ही, डेनमार्क के नियंत्रण में एक द्वीप, ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार की धमकियां, मेक्सिको, क्यूबा, ईरान आदि देशों को भी दी गई हैं।

ट्रम्प के उक्त प्रकार के निर्णयों के चलते अब तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच आपसी सम्बंधो पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत भी अछूता नहीं रहा है एवं हाल ही के समय में भारत के अमेरिका के साथ सम्बन्धों में कुछ खटास आई है। अन्यथा, कुछ समय पूर्व तक भारत एवं अमेरिका एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार माने जाते रहे हैं। विदेशी व्यापार के मामले में अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा साझीदार रहा है। भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात के मामले में भी अमेरिका प्रथम स्थान पर हैं। श्री ट्रम्प द्वारा भारत से अमेरिका को होने वाले विभिन्न उत्पादों के निर्यात पर लागू किए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के उपरांत भारत का विदेश व्यापार कुछ हद्द तक विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है। परंतु, भारत ने इस समस्या का हल निकालने की रणनीति पर तुरंत विचार करना प्रारम्भ किया एवं कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए। ताकि, विशेष रूप अमेरिका को होने वाले वस्त्र एवं परिधान, जेम्स एवं ज्वेलरी, समुद्रीय पदार्थ, खिलौना उद्योग एवं चमड़ा उद्योग जैसे श्रम आधारित उद्योगों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को तुरंत ही रोका जा सके अथवा कम किया जा सके। अन्यथा, की स्थिति में भारत में बेरोजगारी की समस्या एक ज्वलंत समस्या के रूप खड़ी हो सकती थी। भारत ने उक्त उत्पादों के निर्यात हेतु रूस, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया एवं यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के रूप में नए बाजार तलाशे एवं इन देशों को उक्त उत्पादों का निर्यात प्रारम्भ किया। वर्ष 2025 में भारत ने विदेशी व्यापार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों पर गहन वार्ताओं और रणनीतिक अद्यतनों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया है। वर्ष के अंत में, भारत ने यूनाइटेड किंगडम, ओमान एवं न्यूजीलैंड के साथ महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न किए। इसके साथ ही, अफ्रीकी देशों एवं लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी प्रारम्भिक वार्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 माह में भारत से विभिन्न वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि दर को बनाए रखने में सफलता मिली है। सितम्बर एवं अक्टोबर 2025 माह में विशेष रूप से अमेरिका को भारत से होने वाले वस्तुओं के निर्यात पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा था। 27 जनवरी 2026 को तो भारत ने यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देकर इतिहास ही बना डाला है। इस समझौते को 'मदर आफ ऑल डील्स' की संज्ञा दी जा रही है। यह मुक्त व्यापार समझौता 18 वर्षों के उपरांत सम्भव हो सका है। अब तो कनाडा के राष्ट्रपति भी मार्च 2026 माह में भारत आने वाले हैं एवं कुछ क्षेत्रों में मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप दिए जाने की प्रबल सम्भावना है।

भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौतों का विश्व के अन्य देशों को सकारात्मक संदेश गया है। भारत वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न कर रहा है। इससे, समझौता करने वाले देशों के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की सम्भावनाएं प्रबल हो रही हैं क्योंकि इन देशों में आर्थिक प्रगति के तेज होने के चलते इन देशों में खुशहाली आने की सम्भावनाएं बन रही हैं। इस दृष्टि से विभिन्न देशों का भारत के प्रति दृष्टिकोण हाल ही के समय में बदला है एवं वे अब भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं। भारत एक युवा देश है एवं विभिन्न उत्पादों के लिए भारत एक विशाल बाजार के रूप में विश्व के सामने उपलब्ध है। विशेष रूप से इस धरा के दक्षिणी भाग के देश तो अब भारत के वैश्विक स्तर पर इन देशों का नेतृत्व करने के लिए श्रद्धा के भाव से उम्मीद भारी नजरों से देख रहे हैं।

उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भारत के सामने भी कुछ समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। जैसे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डालर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत का लगातार गिरते जाना। एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की क़ीमत 92 रुपए के स्तर को भी पार कर गई है एवं वर्ष 2025 में भारतीय रुपए का लगभग 5 से 6 प्रतिशत के बीच अवमूल्यन हुआ है। दरअसल, यह समस्या, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय पूंजी (शेयर) बाजार से लगातार अपने निवेश को निकालने के चलते खड़ी हुई है। इससे अमेरिकी डॉलर का भारत से बाहर जाने का सिलसिला बढ़ गया है। इस समस्या के हल हेतु भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहा है। साथ ही, भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात को भी गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारत में अमेरिकी डॉलर के आने की मात्रा में वृद्धि हो। यदि भारत को इन प्रयासों में सफलता मिलती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए पर दबाव कुछ कम होगा।

ट्रम्प द्वारा हाल ही के समय में लिए गए निर्णयों के चलते वैश्विक स्तर पर प्रारम्भ हुई उथल पुथल को कम करने के लिए आज विश्व के कई देश भारत की ओर ही देख रहे हैं क्योंकि भारत अपने आप को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाकर इस तरह की समस्याओं का हल निकालने का प्रयास कर रहा है एवं इस कार्य में भारत को कुछ सफलता प्राप्त होती हुई भी दिखाई दे रही है। भारत के पास युवा शक्ति की बेजोड़ उपलब्धता है, विभिन्न क्षेत्रों में इनके कौशल को विकसित कर, भारत आज पूरे विश्व को श्रमबल उपलब्ध करा सकने की क्षमता रखता है और भारतीय सनातन संस्कृति को 'वसुधैव कुटुम्बकम' के भाव के साथ, पूरे विश्व में फैला सकता है ताकि विभिन्न देशों में हो रहे संघर्षों को कम अथवा समाप्त किया जा सके।

यूपी शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेगा : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

लखनऊ **(एजेंसी)**। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेगा क्योंकि राज्य का ध्यान ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने पर केंद्रित है जिसमें बच्चों का विकास सीखने के सकारात्मक माहौल में हो और वे आगे बढ़ सकें। सिंह ने लखनऊ में स्थित सिटी मांटेसरी स्कूल गोल्फ सिटी परिसर के मुख्य भवन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, ''यहां के शिक्षण संस्थान न केवल राज्य के छात्रों के लिए, बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए भी आकर्षण के केंद्र बनकर उभरेंगे।''

उन्होंने कहा कि राज्य का ध्यान केवल स्कूल और कॉलेज खोलने पर नहीं है बल्कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ सीखने के सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ सकें। सिंह ने कहा, ''मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के समन्वित प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करेगा।'' लखनऊ से सांसद सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक व्यापक नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ''हम सभी ने राज्य को पिछले कुछ वर्षों में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते देखा है। बुनियादी ढांचे, निवेश, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने नयी गति हासिल की है।'' उन्होंने सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का उल्लेख करते हुए कहा कि इन दूरदर्शी हस्तियों ने समाज के वंचित वर्गों यानी उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाई, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर पर थे। उन्होंने कहा, ''उन्होंने यह दिखाया कि समाज में समानता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी साधन है।'' मंत्री ने कहा, ''भारत, अपने नाम के अनुरूप हमेशा ज्ञान की खोज में लगा रहा है। यदि आप इसका इतिहास देखें, तो प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत इस ज्ञान-यात्रा के प्रति दृढ़तापूर्वक समर्पित रहा है।''

उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपराओं में शिक्षा को कभी केवल जानकारी हासिल करने का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे चरित्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम समझा गया। उन्होंने कहा कि जब तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय फले-फूले, तब दुनिया के दूर-दराज के हिस्सों से छात्र इन प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए भारत आया करते थे। सिंह ने कहा, ''आपने संभवतः फाह्यान और ह्वेन सांग के नाम सुने होंगे। ये लोग भी भारत आए थे। उन्होंने यह यात्रा इसलिए की क्योंकि इस भूमि में शिक्षा में न केवल ज्ञान प्राप्त करना शामिल है, बल्कि जीवन मूल्यों का समावेश भी शामिल है।''

मध्य पूर्व संकट : लखनऊ और बडगाम में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन, फिलिस्तीन को लेकर भी उठी आवाज

लखनऊ **(एजेंसी)**। 'यौम-ए-कुद्स' के अवसर पर जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम में हजारों लोग एकत्रित हुए और फिलिस्तीन और ईरान के उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए विरोध मार्च निकाला। बडगाम के मरकज़ी इमामबाड़ा में भारी जनसमूह इकट्ठा हुआ, जिसके बाद लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली और बुडगाम के मुख्य चौक की ओर मार्च किया। शुक्रवार को लखनऊ के बारा इमामबाड़ा में जुम्मे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद नकवी ने किया, जिन्होंने अमेरिका की आलोचना करते हुए ईरान से जुड़े संघर्ष को लेकर उसकी कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करने की मांग की।

एएनआई से बात करते हुए कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि ईरान पूरी तरह से बेसहारा है; अमेरिका उस पर बम गिरा रहा है और जनता पर हमले कर रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश इसकी निंदा नहीं कर रहा है। हमारे देश

ने ईरान के प्रति इतना बुरा रवैया अपनाया है कि ईरानी हम पर दया दिखा रहे हैं। उन्होंने भारत को अपने तेल जहाजों को लाने की अनुमति दी है... अमेरिका को हमले करने से रोका जाना चाहिए। अन्यथा, पूरी दुनिया को अमेरिका और इज़राइल का बहिष्कार करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और ईरान का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पहल बहुत देर से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले बात करनी चाहिए थी; अब इसका कोई मतलब नहीं है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकारियों ने रमज़ान की आखिरी जुम्मा नमाज़ के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की।

सम्भल में, नमाज़ के लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालुओं के लिए शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। एएसपी नॉर्थ कुलदीप सिंह ने कहा कि आज होने वाली अलविदा जुम्मा की नमाज़ के संबंध में, हमने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएससी की दो कंपनियों के साथ-साथ अपनी सिविल पुलिस टुकड़ी को भी घटनास्थल पर तैनात किया है... इसके अलावा, मेरे स्तर के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी पूरे दिन, विशेष रूप से नमाज़ के समय, हाई अलर्ट पर रहेंगे और लगातार संपर्क में रहेंगे।

सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग महिला से मारपीट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया जांच के आदेश

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के आजमगढ़ के एक सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आई बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने अस्पताल के डॉक्टर और सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो वायाल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं।

उन्होंने एक्स पोस्ट कहा कि आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय में वृद्ध महिला व तीमारदार के साथ अभद्र व्यवहार संबंधी वायरल वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, आजमगढ़ को मौके पर पहुंचकर उक्त प्रकरण की जांच, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने एवं 3 दिन में जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मरीजों व तीमारदारों के साथ अभद्र व्यवहार की घटना कतई स्वीकार नहीं है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्पताल में आने वाला प्रत्येक मरीज हमारे लिए भगवान का रूप है। उक्त प्रकरण की जांच आख्या एवं सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

आप को बता दें कि बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि डॉक्टर ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और डॉक्टर तथा सुरक्षाकर्मियों ने मां-बेटे के साथ मारपीट कर दी।

पीड़ित बेटे का कहना है कि इस घटना में उसकी बुजुर्ग मां को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजनों और अन्य लोगों में नाराजगी देखी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मजार से लौट रही महिला संग गैंगरेप, पुलिस ने बताया मामला संदिग्ध, जांच जारी

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शाहबाबा मजार पर मत्था टेककर घर लौटते समय तीन लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने उसे कार में बैठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार दोपहर वह शाहगंज क्षेत्र के बड़ागांव स्थित मजार पर दर्शन के लिए गई थी। देर शाम घर लौटते समय रास्ते में गांव के ही तीन लोग मिले, जिन्होंने उसे घर तक छोड़ने का कहकर कार में बैठा लिया।

महिला का आरोप है कि रास्ते में आरोपियों ने कार में उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और फिर उसे एक सुनसान स्थान पर ले जाकर झाड़ियों में ले गए। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि घटना के बाद आरोपी उसे रेलवे फाटक के पास छोड़कर फरार हो गए।

इस मामले में अजीत सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है। महिला द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है, उन्होंने पहले ही महिला के खिलाफ पैसे के लेनदेन को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है।

इज़राइल-ईरान युद्ध से यूपी का यूरोप से कारोबार लड़खड़ाया!

दांव पर लगा हजारों करोड़, खाड़ी देशों से ऑर्डर रुके होने से भारी नुकसान

लखनऊ **(एजेंसी)**। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत के निर्यात कारोबार पर भी पड़ने लगा है। खासकर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर का चमड़ा उद्योग इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खाड़ी देशों में अनिश्चितता के कारण कई विदेशी खरीदारों ने अपने ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं, जिससे निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

व्यापारियों के मुताबिक दुबई, यूएई और ओमान जैसे देशों के लिए भेजे जाने वाले बड़े ऑर्डर अचानक होल्ड पर चले गए हैं। केवल दो दिनों के भीतर ही कानपुर के करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात ऑर्डर रुक गए हैं। वहीं चमड़ा उद्योग से जुड़े कुल मिलाकर करीब 1, 000 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्रभावित होने की बात सामने आ रही है।

खाड़ी देशों में ईद के दौरान भारतीय उत्पादों की मांग हर साल बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कानपुर के कई निर्यातकों ने पहले से ही बड़े ऑर्डर ले रखे थे और फैक्ट्रियों में उत्पादन तेज कर दिया गया था। यहां से बड़ी मात्रा में चमड़े के जूते, सेफ्टी शूज, बैग, बेल्ट और अन्य लेदर उत्पाद गल्फ देशों में भेजे जाते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण विदेशी खरीदारों ने फिलहाल अपने ऑर्डर रोक दिए हैं और कुछ जगहों पर

शिपमेंट भी अटक गए हैं।

निर्यातकों का कहना है कि मौजूदा हालात उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। यूएई, दुबई और ओमान लंबे समय से भारतीय चमड़ा उत्पादों के बड़े बाजार रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन देशों से नए ऑर्डर मिलने की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

व्यापार जगत से जुड़े लोगों का अनुमान है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो आने वाले 10 से 15 दिनों में भारतीय निर्यातकों को 1, 500 से 2, 000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है। कानपुर के चमड़ा निर्यातकों का कहना है कि इस संकट से उबरने में उद्योग को कई महीने लग सकते हैं। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय हालात पर नजर रखते हुए व्यापारी आगे की रणनीति तय करने में जुटे हैं।

उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट वायरल वीडियो सें कोड ठगी, 37 लाख जुटाए - पुलिस ने अकाउंट किया फ्रीज

पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हुए तरुण हत्याकांड से जुड़ा एक नया और संदिग्ध मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक महिला के इंटरव्यू का वीडियो वायरल होने के बाद उस पर क्यूआर कोड जोड़कर लोगों से आर्थिक मदद मांगी गई। बताया जा रहा है कि इस तरीके से कुछ ही दिनों में करीब 37 लाख रुपये एक बैंक खाते में जमा हो गए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और संबंधित बैंक खाते को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है।

4 मार्च 2026 को होली के दिन पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की ब्लॉकॉलोनी में एक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया था। बताया गया कि रंग से भरे गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि 26 वर्षीय तरुण कुमार की हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में कार्रवाई के तहत आरोपी परिवार से जुड़े घरों पर नगर निगम की ओर से कार्रवाई भी की गई।

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खाते को फ्रीज करवा दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों से संपर्क कर वायरल पोस्ट और वीडियो हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो अपलोड करने वाला व्यक्ति कौन है और क्यूआर कोड के जरिए पैसे जुटाने के पीछे उसका असली मकसद क्या था।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने कहा है कि वीडियो में दिख रही महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके इंटरव्यू का इस्तेमाल लोगों से पैसे इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। पुलिस के अनुसार महिला का हत्या के मामले में कोई प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं पाया गया है।

एलपीजी की कमी के चलते देशभर में इंडक्शन कुकटॉप धड़ाधड़ बिक रहे, होटलों में मिट्टी का तेल और कोयला से बनेगा खाना!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और समुद्री मार्ग बाधित होने के कारण भारत में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर आशंका का माहौल बन गया है। इस स्थिति ने देशभर में घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में गैस सिलेंडर की बुकिंग में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे वितरण प्रणाली पर दबाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर लोग वैकल्पिक साधनों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं, जिसके चलते इंडक्शन चूल्हों और अन्य बिजली आधारित खाना पकाने के उपकरणों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जा रही है।

ई-कॉमर्स मंचों पर इंडक्शन चूल्हों की मांग पिछले कुछ दिनों में कई गुना बढ़ गई है। कुछ मंचों पर बिक्री चार-पांच गुना तक पहुंच गई है, जबकि कुछ स्थानों पर मांग बीस गुना तक बढ़ने की खबर है। दिल्ली, कोलकाता और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यह बढ़ोतरी और भी अधिक देखी जा रही है। त्वरित आपूर्ति सेवाओं यानि क्विक कॉमर्स मंचों और किराना दुकानों पर भी इंडक्शन चूल्हों की बिक्री लगभग दस गुना तक बढ़ी है। घरेलू उपभोक्ता एलपीजी की अनिश्चितता को देखते हुए बैकअप व्यवस्था के रूप में बिजली से चलने वाले उपकरण खरीद रहे हैं।

उधर, एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी से कई जगह बुकिंग प्रणाली भी प्रभावित हुई है। उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि फोन आधारित बुकिंग, मोबाइल एप और एसएमएस से बुकिंग वाले प्लेटफार्म पर सर्वर डाउन के संदेश आ रहे हैं। वितरकों के अनुसार सामान्य दिनों की तुलना में बुकिंग की संख्या लगभग दस गुना तक बढ़ गई है, जिसके कारण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है और पूरी तरह से आपूर्ति बंद नहीं हुई है। हालांकि लोग एलपीजी डीलरों

के यहां लाइनों में लगे हुए हैं और शिकायतें कर रहे हैं।

उधर, व्यावसायिक उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर हालांकि असर पड़ा है। होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सेवाओं को सीमित मात्रा में गैस दी जा रही है, जिससे कई कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। केरल में उद्योग संगठनों ने आशंका जताई है कि गैस की कमी के कारण लगभग चालीस प्रतिशत रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत उपायों के तहत केरोसिन और कोयले को अस्थायी रूप से खाना पकाने के विकल्प के रूप में फिर से अनुमति दी है। राज्यों को अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन आवंटित किया गया है और होटल उद्योग को एक माह के लिए बायोमास, आरडीएफ पेलेट और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपयोग की अनुमति देने को कहा गया है।

हम आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच अंतराल को भी बढ़ाकर पैंतालीस दिन कर दिया है ताकि मांग को नियंत्रित किया जा सके और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश में रोजाना लगभग पचास लाख सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं और पेट्रोल, डीजल सहित अन्य ईंधनों की आपूर्ति सामान्य है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि घबराकर अनावश्यक बुकिंग न करें।

इस बीच, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण भी पकड़ा गया है। पुलिस ने एक व्यक्ति के घर पर छापा मारकर अठारह भरे और चौदह खाली सिलेंडर बरामद किए। आरोप है कि वह विभिन्न वितरकों से सिलेंडर खरीदकर स्थानीय लोगों को अधिक कीमत पर बेच रहा था। अधिकारियों ने इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन बताते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई आशंकाओं ने देश में एलपीजी को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन सरकार का कहना है कि आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह संकट लोगों को बिजली आधारित वैकल्पिक खाना पकाने के साधनों की ओर भी तेजी से प्रेरित कर रहा है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच चौथी बार हुई जयशंकर-अराघची की बातचीत, होर्मुज से मिल रही अच्छी खबर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष सैयद अब्बास अराघची से बात की। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद यह दोनों नेताओं की चौथी बातचीत थी। जयशंकर और अराघची के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे 28 व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद से चौथी बार हुई बातचीत भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच बीती रात फोन पर बातचीत हुई। बीती 28 फरवरी को जब अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, उसके बाद भी जयशंकर ने अराघची से बात की थी। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच बीती 5 मार्च और फिर 10 मार्च को भी

दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। बीते करीब 15 दिनों में दोनों के बीच गुरुवार रात को चौथी बार बात हुई है।

होर्मुज जलडमरूमध्य से मिल रही अच्छी खबर

विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, 'कल रात ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ एक और बातचीत हुई। इस बातचीत में द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ ब्रिक्स से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।' भारत, होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक शिपिंग मार्ग से भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और इस्राइल के साथ संघर्ष बढ़ने के बाद तेहरान ने इस मार्ग को आंशिक रूप से अवरुद्ध कर दिया है। जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। हालांकि गुरुवार को एक अच्छी खबर सामने आई कि एक भारतीय जहाज सुरक्षित भारत पहुंचा। इसे भारत के कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है।

ईरान ने जारी किया बयान

ईरान की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अराघची ने अपने भारतीय समकक्ष को अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए हमलों से पैदा हुई स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया की स्थिरता और सुरक्षा पर इसके परिणामों के बारे में जानकारी दी। ईरानी विदेश मंत्री ने जयशंकर के सामने आत्मरक्षा के वैध अधिकार के इस्तेमाल के तेहरान के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया।

बयान में कहा गया, अराघची ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों और संगठनों द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य आक्रमण की निंदा किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। बहुपक्षीय सहयोग विकसित करने के एक मंच के रूप में ब्रिक्स की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने मौजूदा समय में क्षेत्र और दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा का समर्थन करने में ब्रिक्स की अहम भूमिका पर जोर दिया।

लखनऊ और बडगाम में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन, Palestine को लेकर भी उठी आवाज

'यौम-ए-कुद्स' के अवसर पर जम्मू एवं कश्मीर के बडगाम में हजारों लोग एकत्रित हुए और फिलिस्तीन और ईरान के उत्पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए विरोध मार्च निकाला। बडगाम के मरकज़ी इमामबाड़ा में भारी जनसमूह इकट्ठा हुआ, जिसके बाद लोगों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली और बुडगाम के मुख्य चौक की ओर मार्च किया। शुक्रवार को लखनऊ के बारा इमामबाड़ा में जुम्मे की नमाज के बाद लोगों के इकट्ठा होने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद नकवी ने किया, जिन्होंने अमेरिका की आलोचना करते हुए ईरान से जुड़े संघर्ष को लेकर उसकी कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करने की मांग की। एएनआई से बात करते हुए कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि ईरान पूरी तरह से बेसहारा है; अमेरिका उस पर बम गिरा रहा है और जनता पर हमले कर रहा है। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारा देश इसकी निंदा नहीं कर रहा है। हमारे देश ने ईरान के प्रति इतना बुरा रवैया अपनाया है कि ईरानी हम पर दया दिखा रहे हैं। उन्होंने भारत को अपने तेल जहाजों को लाने की अनुमति दी है... अमेरिका को हमले करने से रोका जाना चाहिए। अन्यथा, पूरी दुनिया को अमेरिका और इज़राइल का बहिष्कार करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और ईरान का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह पहल बहुत देर से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पहले बात करनी चाहिए थी; अब इसका कोई मतलब नहीं है। इस बीच, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकारियों ने रमज़ान की आखिरी जुम्मा नमाज़ के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की।

सम्भल में, नमाज़ के लिए इकट्ठा हुए श्रद्धालुओं के लिए शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। एएसपी नॉर्थ कुलदीप सिंह ने कहा कि आज होने वाली अलविदा जुम्मा की नमाज़ के संबंध में, हमने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएससी की दो कंपनियों के साथ-साथ अपनी सिविल पुलिस टुकड़ी को भी घटनास्थल पर तैनात किया है... इसके अलावा, मेरे स्तर के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी पूरे दिन, विशेष रूप से नमाज़ के समय, हाई अलर्ट पर रहेंगे और लगातार संपर्क में रहेंगे।

गैस की बढ़ती कीमतों और किल्लत के खिलाफ काँग्रेस का हल्लाबोल; दाम कम करने की मांग

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध जैसी स्थितियों का असर अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इसी बीच, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों और बाजार में पैदा की गई गैस की 'कृत्रिम किल्लत' के खिलाफ काँग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। भिवंडी शहर काँग्रेस की ओर से शहराध्यक्ष रशीद ताहीर मोमिन के नेतृत्व में गुरुवार को दोपहर में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। यह आंदोलन भिवंडी शहर के मुख्य काँग्रेस कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। आंदोलन के दौरान काँग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की कमर टूट गई है। शहर में गैस की आपूर्ति में आ रही बाधाओं और जानबूझकर पैदा की गई कमी पर भी रोष व्यक्त किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं और काँग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने खाली सिलेंडर दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

काँग्रेस शहराध्यक्ष रशीद ताहीर मोमिन ने मांग की है कि सरकार गैस की बढ़ती कीमतों को तुरंत वापस ले और गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करे ताकि सर्वसामान्य नागरिकों को इस महंगाई से राहत मिल सके।

सरकारी जमीन हड़पने का आरोप, बिल्डर समेत कई लोगों पर केस दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने के आरोप में पुलिस ने बिल्डर, जमीन मालिक और रजिस्टर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला करोड़ों रुपये की जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) के उप जिला अधिकारी कृष्णकांत नागोराव चीकुंते ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अजय वेदप्रकाश छाब्रा, रजनी अजय छाब्रा, मेसर्स शुभारंभ प्रॉपर्टीज ट्रस्ट से जुड़ी रीना रत्नेश जैन व अन्य हिस्सेदार, कुल मुख्तार धारक मंगेश महादेव कोलेकर, तत्कालीन प्रभारी सह दुय्यम निबंधक बी.एस. गायकवाड़, और कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों ने मिलकर सरकारी जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कथित हेराफेरी की। आरोप है कि इन लोगों ने शाहापुर तालुका के विरवाड़ी गांव में स्थित सर्वे 208/1, 241/3,292/5,416/2 के प्लॉट क्रमांक 194 के क्षेत्र 3158 चौ. मीटर,192 के 0874 चौ.मीटर (194 व 192 के कुल 4832 चौं मीटर व प्लांट क्रमांक 100 के 3157 चौं मीटर सरकारोंजमीन के दस्तावेजों में गलत जानकारी जोड़कर जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की। शिकायत के अनुसार आरोपियों व तत्कालीन रजिस्टर अधिकारियों ने पुराने दस्तावेजों और गलत प्रविष्टियों का सहारा लेकर जमीन के स्वामित्व को लेकर भ्रम पैदा किया और सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयास किया। इस मामले में सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालय से जुड़े कुछ कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4), 336(2), 338, 340(1), 62, 198 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मामला पहले शाहापुर क्षेत्र से जुड़ा है और वहां से प्राप्त एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक (अपराध) अतुल अडुंकर कर रहे हैं।

भिवंडी मनपा अवैध बैनर-पोस्टर पर सख्त, दो अलग-अलग मामले दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में अवैध बैनर-पोस्टर लगाने के खिलाफ भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका ने सख्ती शुरू कर दी है। बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाने के दो मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों ही मामलों में महाराष्ट्र मालमत्ता विकृतीकरण प्रतिबंध अधिनियम 1995 तथा मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

पहले मामले में भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता भिवंडी मनपा के प्रभाग समिति क्रमांक तीन के बीट निरीक्षक सूरज गायकवाड़ ने बताया कि धामणकर नाका भाजी मार्केट रोड से मानसरोवर रोड, कामतघर क्षेत्र में 'गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टिट्यूट' के नाम से कई विज्ञापन बैनर लगाए गए थे। जांच में सामने आया कि इन बैनरों को पालिका प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों और बिजली के खंभों पर लगाया गया था। इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे मामले में शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रभाग समिति एक के सहायक आयुक्त मकसूम अहमद शेख ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बंजारपट्टी नाका क्षेत्र में इलेक्ट्रिक पोल पर 3□4 फुट के कई बैनर लगाए गए थे, जिनके माध्यम से एक इंटरनेशनल स्कूल के एडमिशन का प्रचार किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि इन बैनरों को भी महानगरपालिका की अनुमति के बिना लगाया गया था, जिससे शहर की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है।पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनपा अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शहर में बिना अनुमति बैनर-पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रांस हार्बर लाइन पर रविवार को मेगा ब्लॉक

मध्य रेल, मुंबई मंडल , रविवार, दिनांक 15.03.2026 को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए ठाणे और वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच ट्रांस हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक परिचालित करेगा। ब्लॉक कार्य इस प्रकार रहेगाः ट्रांस-हार्बर लाइनः ठाणे और वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच अप और डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन 11.10 बजे से 16.10 बजे तक ब्लॉक अवधि के दौरान वाशी/नेरुल और ठाणे स्टेशनों के बीच अप और डाउन ट्रांस-हार्बर लाइन सेवाएं रद्द रहेंगी। ठाणे से वाशी/नेरुल/पनवेल जाने वाली डाउन लाइन की ट्रेनें सुबह 10:35 बजे से शाम 16:07 बजे तक और पनवेल/नेरुल/वाशी से ठाणे जाने वाली अप लाइन की ट्रेनें सुबह 10:25 बजे से शाम 16:09 बजे तक रद्द रहेंगी।

भिवंडी में 23 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी।भिवंडी शहर के गोपालनगर इलाके से क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। जिसके पास से पुलिस 110 ग्राम मादक प्रदार्थ बरामद किया है।जिसकी कीमत करीब 23.01 लाख रुपये बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार भिवंडी क्राइम ब्रांच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नशे के सौदागर स्थानीय गोपाल नगर इलाके में मादक प्रदार्थ की बिक्री करने वाले है।जिसके बाद उक्त पुलिस ने 11 मार्च की रात करीब 9:05 बजे दादासाहेब दांडेकर विद्यालय के सामने जाल बिछाकर दो आरोपियों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 110 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) पाउडर बरामद हुआ जिसकी बाजार कीमत करीब 23.01 लाख रुपये बताई गई है।क्राइम ब्रांच यूनिट-2 के पुलिस हेड कांस्टेबल नितीन नंदीवाले की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8(क), 22(ब) और 29 के तहत मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।जिनका नाम वसीम सलीम शेख (42), निवासी कल्याण और सारीम शब्बीर मोमीन (23), निवासी बंदर मोहल्ला, भिवंडी है।पूछताछ पर आरोपियों ने पुलिस को बताया कि यह ड्रग्स उन्होंने जैब अमजद पठाण नामक व्यक्ति से खरीदी थी और बिक्री के इरादे से अपने पास रखी थी।मामले की जांच क्राइम ब्रांच यूनिट-2 के पुलिस उपनिरीक्षक रविंद्र वी. पाटिल कर रहे हैं। पुलिस अब इस मामले में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

महिला आयोग के अध्यक्ष को बुजुर्ग महिला ने भेजा पत्र,न्याय की लगाई गुहार

कहा परिचित महिला ने उसके घर में घुसकर की जान से मारने व गहने चुराने की कोशिश

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। 58 वर्षीय महिला के घर में अकेले होने का फायदा उठाते हुए 35 वर्षीय महिला गहने चुराने के इरादे से बुजुर्ग महिला के घर में घुस गई, उसे बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया और गला घोंटकर उसकी हत्या करने की कोशिश की।उक्त हृदयविदारक घटना भिवंडी तालुका के लोनाड के देवरुंग पाड़ा की है।इस मामले में पड़घा पुलिस स्टेशन में बुजुर्ग महिला की पिटाई करने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।लेकिन बुजुर्ग महिला ने अपने साथ हुए जानलेवा हमले की शिकायत महिला आयोग से करते हुए उस पर गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है।

महिला आयोग को भेजे पत्र में बुजुर्ग महिला

पार्वती तुकाराम गोडे (58) ने बताया कि 26 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 3:30 बजे घर में अकेली सो रही थी, तब उसकी परिचित उसी के गांव की रहने वाली प्रमिला कैलाश गोडे (35) ने घर में किसी की मौजूदगी न होने का फायदा उठाते हुए अचानक गहने चुराने के इरादे से घर में घुसकर उसके सीने पर बैठ गई, उसे गालियां दीं और मुक्कों से बुरी तरह पीटा। शिकायतकर्ता पार्वती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने अलमारी की चाबियों से गला घोंटकर उसे जान से मारने की कोशिश की, जिससे खून बहने लगा। इसी दौरान वह चीखी और किसी तरह घर का दरवाजा खोलकर खुद को छुड़ा लिया। पार्वती गोडे ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने इसे संज्ञेय अपराध बताते हुए भी सिर्फ गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में दर्ज किया है। उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया है कि आरोपी महिला ने उसके घर में घुसकर उनके गहने चुराने की कोशिश की और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। पीड़ित पार्वती गोडे ने मांग की है कि आरोपी महिला के खिलाफ गंभीर संज्ञेय अपराध दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए।

भिवंडी में बिल्डर पर 4.12 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

तीन संचालकों पर केस दर्ज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। शहर में सस्ते घर देने का लालच देकर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेने और वर्षों बाद भी फ्लैट न देने के मामले में पुलिस ने एक बिल्डर कंपनी के तीन संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि बिल्डरों ने 12 से अधिक निवेशकों से करीब 4 करोड़ 12 लाख 9 हजार 590 रुपये की राशि ली, लेकिन 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो फ्लैट दिए और न ही पैसा लौटाया। नारपोली पुलिस स्टेशन के अनुसार माणिक शिवाजी म्हेत्रे (41), निवासी घाटकोपर ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि वाधवा बिल्डकॉन एलएलपी के संचालक अंकित सुरेश वाधवा (36), आशिष सुरेश वाधवा (34) और सुरेश वाधवा ने मिलकर रेलवे स्टेशन के पास 'वाधवा रोडिशिया' और 'वाधवा फ्लोरेंस' नामक आवासीय परियोजनाएं शुरू की थीं। शिकायत के अनुसार इन परियोजनाओं में निवेशकों को आकर्षक योजनाओं के माध्यम से सस्ते घर देने का भरोसा दिलाया गया था। शिकायतकर्ता माणिक म्हेत्रे का आरोप है कि उनसे 26 लाख 57 हजार 400 रुपये लिए गए, जबकि अन्य 12 निवेशकों से मिलाकर कुल 4.12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की गई। पीड़ितों का कहना है कि वर्ष 2013 से अब तक परियोजना अधूरी पड़ी है और निवेशकों को न तो फ्लैट दिए गए और न ही उनकी जमा राशि वापस की गई। इसके बाद पीड़ितों ने नारपोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 34 तथा महाराष्ट्र ठेवीदारों के हित संरक्षण अधिनियम 1999 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक विद्या पाटील कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, भिवंडी कोर्ट का फैसला

भिवंडी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वाले आरोपी की पहचान संदेश गणपत खरपडे (19) के रूप में हुई है, जो पालघर जिला के वाडा तालुका के तिलसा गांव का निवासी है। जानकारी के अनुसार 5 अगस्त 2018 को आरोपी ने वाडा तालुका के एक गांव में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद वाडा पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस प्रकरण की सुनवाई भिवंडी की अदालत में चल रही थी। सरकारी वकील विजय मुंढे ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। भिवंडी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. के. कारंडे ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस संवेदनशील मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक गोविंद बोराडे ने की थी। अदालत के इस फैसले को पीड़िता के परिवार के लिए महत्वपूर्ण न्याय माना जा रहा है।

गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारु रखने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में नियंत्रण कक्ष; जिला स्तरीय समितियों का गठन

पिछले छह महीनों की तुलना में अधिक मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध

मुंबई। ईरान-इज़राइल युद्ध की पृष्ठभूमि में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा न आए और संभावित कमी की स्थिति में बेहतर समन्वय हो सके, इसके लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित करने का निर्णय लिया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर ने संबंधित सभी एजेंसियों को राज्यभर में एलपीजी आपूर्ति सुचारु रखने तथा वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से जारी रहेगी और किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।

मार्च महीने में पिछले छह महीनों की तुलना में अधिक मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि में घरेलू गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन

घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में बाधा न आए और संभावित कमी की स्थिति में समन्वय सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जिला स्तर पर विशेष समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा सभी सरकारी गैस कंपनियों के अधिकारी शामिल होंगे।

इन समितियों की मुख्य जिम्मेदारी गैस आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।

मुंबई-ठाणे राशनिंग क्षेत्र में नियंत्रक (रेशनिंग) के अधीन एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें पुलिस उप आयुक्त और उपनियंत्रक (रेशनिंग) शामिल होंगे। मुंबई और ठाणे शहर के सभी उपायुक्तों के साथ समन्वय सह-पुलिस आयुक्त (प्रशासन) द्वारा किया जाएगा।

प्रशासन ने वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें कोयला, मिट्टी का तेल आदि विकल्पों पर विचार किया जाएगा, हालांकि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रहेगा। जिला स्तरीय समितियों को होटल और रेस्टोरेंट संगठनों के साथ बैठक कर वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अत्यावश्यक सेवाओं को एलपीजी आपूर्ति में प्राथमिकता

अस्पताल, सरकारी छात्रावास, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के मेस, मध्याह्न भोजन योजना, सरकारी आश्रमशालाएं आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं देने वाली संस्थाओं को घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। ऐसी संस्थाओं की सूची भी जारी की जाएगी तथा इनके लिए अलग प्राथमिकता क्रम तय किया जाएगा।

गैस आपूर्ति को लेकर अफवाहें न फैलें, इसके लिए प्रतिदिन रेडियो, एफएम, दूरदर्शन तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय तथा जिला समितियां जिम्मेदारी निभाएंगी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी और भ्रामक खबरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

तेल कंपनियों को गैस बुकिंग ऐप और मिस्ड कॉल सेवाओं में आने वाली तकनीकी समस्याओं को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य, संभाग, जिला और तालुका स्तर पर नियंत्रण कक्ष शुरू किए जाएंगे और शिकायत निवारण के लिए व्हाट्सऐप सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

आगामी धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक संस्थाओं को एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

गैस आपूर्ति को लेकर नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट न हो, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत सदस्यों की मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं। एलपीजी परिवहन करने वाले वाहनों तथा गैस एजेंसियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दी गई है।

जिला प्रशासन, राशनिंग नियंत्रक और तेल कंपनियों को प्रतिदिन स्टॉक की स्थिति और अद्यतन रिपोर्ट राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को भेजना अनिवार्य किया गया है।

राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं

महाराष्ट्र में प्रतिदिन औसतन लगभग 9,000 मीट्रिक टन एलपीजी की मांग होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया गया है और पिछले दो दिनों में दैनिक उत्पादन 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसलिए राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन तथा भंडार उपलब्ध है।

व्यावसायिक एलपीजी के मामले में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता तय की गई है। इसके तहत अस्पताल, स्कूलों की मध्याह्न भोजन योजना, आश्रमशालाएं, सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) तथा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के मेस जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इसी प्रकार राज्य में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बाजार की मांग पूरी करने के लिए राज्य की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और प्रतिदिन लगभग 15,000 किलोलीटर पेट्रोल तथा 38,000 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

राशन वितरण विभाग की बड़ी कार्रवाई

वर्ली में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़

मुंबई। राशन वितरण विभाग ने वर्ली क्षेत्र में घरेलू और वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सिलेंडर जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में पता चला कि गैस सिलेंडरों को आवासीय क्षेत्र में खतरनाक तरीके से संग्रहित किया जा रहा था और उन्हें कालाबाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। नियंत्रक राशन वितरण कार्यालय की मोबाइल टीम और कार्यालय क्रमांक 21 के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि वर्ली नाका के गणपतराव कदम मार्ग स्थित 'सूरज वल्लभदास चॉल' क्षेत्र में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर ऊंचे दामों पर बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत छापा मारकर अवैध रूप से रखे गए सिलेंडरों को जब्त कर लिया।

इस कार्रवाई में एचपी गैस कंपनी के 5 किलोग्राम के 6 भरे हुए और 58 खाली सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा सुपर गैस कंपनी के 4 किलोग्राम के 64 भरे हुए सिलेंडर तथा 12 किलोग्राम के 19 भरे हुए सिलेंडर भी बरामद किए गए। साथ ही 12, 4 और 2 किलोग्राम के विभिन्न आकार के 25 खाली सिलेंडर भी मौके से पाए गए। अधिकारियों के अनुसार इन सिलेंडरों को अवैध रूप से भरकर कालाबाजार में बिक्री के लिए रखा गया था। जब्त की गई सभी सामग्री को आगे की आपराधिक कार्रवाई के लिए वर्ली पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार आवासीय क्षेत्रों में सिलेंडरों का अवैध भंडारण और बिक्री करना अत्यंत खतरनाक है और इससे नागरिकों के जीवन को बड़ा खतरा हो सकता है।

यह कार्रवाई नियंत्रक राशन वितरण चंद्रकांत डांगे के मार्गदर्शन में की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभाग की टीमें 24 घंटे सतर्क हैं।

जल जीवन मिशन के कार्य जल्द होंगे पूर्ण - मंत्री गुलाबराव पाटिल

मुंबई, दिनांक 13 : राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं के कुछ कार्य जो आंशिक रूप से रुके हुए हैं, उन्हें केंद्र से निधि प्राप्त होते ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। यह जानकारी जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल ने विधानसभा में नियम 293 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव के उत्तर में दी।

मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार की निधि में 50-50 प्रतिशत की भागीदारी है। राज्य की कार्ययोजना के अनुसार महाराष्ट्र में 50 हजार से अधिक जलापूर्ति योजनाएं प्रस्तावित की गई थीं। इनमें से अब तक लगभग 26 हजार योजनाएं, अर्थात लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र से निधि प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार ने विशेष रूप से राज्य निधि उपलब्ध कराई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के खर्च के लिए राज्य सरकार ने 4831 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

मंत्री पाटिल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और पूरे देश के लिए लगभग 8 लाख करोड़ रुपये की निधि को मंजूरी दी गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि केंद्र से अपेक्षित निधि जल्द प्राप्त हो जाती है, तो राज्य में 75 से 99 प्रतिशत तक पूर्णता के चरण में पहुंच चुकी लगभग 7 हजार योजनाएं तथा 50 से 75 प्रतिशत प्रगति वाली लगभग 7 हजार योजनाएं अगले 5 से 6 महीनों में पूरी की जा सकती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सभी राज्यों के जलापूर्ति मंत्रियों की बैठक लेकर आवश्यक निधि और प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिए हैं।

महिला क्रिकेट में 'नारी शक्ति' की क्रांति बीबीसी रिपोर्ट में खुलासा- दोगुनी हुई भागीदारी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। 'बीबीसी और कलेक्टिव न्यूज़रूम' द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में महिला क्रिकेट का तेजी से विकास हुआ और 2020 के बाद से 14 राज्यों में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हो गई है। इस अध्ययन में 10, 000 से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि 2020 में क्रिकेट खेलने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है। वहीं युवा महिलाओं में यह बढ़ोतरी और भी तेजी से हुई है। इसमें 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में यह छह प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गया है।

अध्ययन के अनुसार, ''15 से 24 वर्ष की हर चार में से एक युवती ने खेल को करियर विकल्प के रूप में सोचने पर विचार किया है। '' हाल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। टीम ने अपना पहला वनडे विश्व कप जीता और लगभग एक दशक में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को तीन मैच की द्विपक्षीय टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में हराया। खेल की लोकप्रियता बढ़ाने में इस सफलता का भी योगदान हो सकता है। क्रिकेट ने पारंपरिक खेल कबड्डी को भी काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है जो लंबे समय से भारत के ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय रहा है। अध्ययन में कहा गया, ''जिन राज्यों में अध्ययन किया गया, उनमें महिलाओं के बीच सबसे अधिक खेले जाने वाले खेल के रूप में क्रिकेट अपनी स्थिति और मजबूत कर चुका है। 2020 में यह कबड्डी से केवल मामूली अंतर से आगे था लेकिन अब क्रिकेट काफी आगे पहुंच गया है। '' इसके अनुसार, ''अधिकांश क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ी है। सर्वे किए गए राज्यों में से केवल दो को छोड़कर सभी में महिलाओं द्वारा क्रिकेट खेलने की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में भागीदारी 10 गुना बढ़कर एक से 10 प्रतिशत हो गई है। साथ ही इन राज्यों में क्रिकेट खेलने में महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर भी कम हुआ है। '' अध्ययन से यह भी पता चला कि तीन पुरुषों के मुकाबले अब एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जबकि 2020 में यह अनुपात पांच पुरुष और एक महिला का था।

करियर के संदर्भ में 15 से 24 वर्ष की 26 प्रतिशत युवतियों ने खेल में करियर बनाने पर विचार किया है जो 2020 में 16 प्रतिशत था। सबसे अधिक प्रतिशत तमिलनाडु (27 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (19 प्रतिशत) और मेघालय (19 प्रतिशत) में दर्ज किया गया। सर्वे में शामिल महिलाओं के बीच बैडमिंटन में भी भागीदारी बढ़ी है, विशेषकर पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके अनुसार अगर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का सही समाधान किया जाए तो और अधिक महिलाएं खेलों की ओर आकर्षित हो सकती हैं।

अदाणी समूह के बांड की जबरदस्त डिमांड अमेरिकी संस्थागत निवेशक भी बढ़ा रहे हिस्सेदारी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक बाजारों में आई अस्थिरता के बीच निवेशकों ने अदाणी समूह के डॉलर में जारी बॉन्ड बेचने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। समूह की बंदरगाह कंपनी एपीएसईजेड की तरफ से बॉन्ड पुनर्खरीद की पेशकश के बावजूद ऐसा निवेशक रुझान देखने को मिला है। मामले से परिचित सूत्रों ने कहा कि अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने नकद निविदा प्रस्ताव के जरिये अमेरिकी डॉलर में जारी दो श्रृंखलाओं के जल्द परिपक्व होने वाले बॉन्ड का कुछ हिस्सा वापस खरीद लिया। इससे कंपनी के बकाया ऋण में लगभग 19.95 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कमी आई।

इस पेशकश के तहत वर्ष 2027 में परिपक्व होने वाले चार प्रतिशत ब्याज दर वाले 34.51 करोड़ डॉलर तक के बॉन्ड और वर्ष 2031 में परिपक्व होने वाले 3.10 प्रतिशत ब्याज दर वाले 15 करोड़ डॉलर तक के बॉन्ड शामिल थे। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 49.5 करोड़ डॉलर तक की संभावित पुनर्खरीद की पेशकश की गई थी। हालांकि बॉन्डधारकों ने अपेक्षा से कहीं कम मात्रा में बॉन्ड वापस बेचने की पेशकश की। आखिरकार कंपनी ने 2027 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड में से 10.21 करोड़ डॉलर और 2031 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड में से 9.75 करोड़ डॉलर स्वीकार किए। इस तरह 60 प्रतिशत से अधिक निवेशकों ने अपने बॉन्ड अपने पास ही रखने का फैसला किया और पुनर्खरीद प्रस्ताव के जरिये बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना।

सूत्रों ने कहा कि प्रारंभिक समय-सीमा के बाद निवेशकों ने 2027 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड में पांच लाख डॉलर और 2031 में परिपक्व होने वाले बॉन्ड में 21.3 लाख डॉलर अतिरिक्त पेश किए। इस तरह कुल बॉन्ड पुनर्खरीद बढ़कर 19.95 करोड़ डॉलर हो गई। यह कदम देश की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह संचालन कंपनी एपीएसईजेड की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी अपने बही-खाते में उपलब्ध अतिरिक्त नकदी का उपयोग कर धीरे-धीरे कर्ज घटा रही है।

अदाणी समूह की कंपनी ने हाल के वर्षों में पुनर्वित्तपोषण और चयनित पुनर्खरीद के जरिए अपने कर्ज ढांचे को पुनर्गठित किया है और इसके साथ अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक अपनी पहुंच भी बनाए रखी है। इस लेनदेन से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, ''हमें उम्मीद थी कि अधिक निवेशक बॉन्ड वापस बेचेंगे लेकिन प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही।'' सूत्रों ने कहा कि अमेरिका स्थित कुछ संस्थागत निवेशक द्वितीयक बाजार में भी अदाणी समूह से जुड़े बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं।

सुमित अंतिल ने रचा इतिहास जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पैरालंपिक खेलों में दो बार के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को यहां विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में शीर्ष पोडियम स्थान हासिल किया। दिन की मुख्य स्पर्धा निश्चित रूप से पुरुषों की भाला फेंक (एफ43, एफ44, एफ64) स्पर्धा थी जिसमें तोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में लगातार दो स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतिल ने 69.25 मीटर के थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल करके भारतीय टीम की अगुआई की।

पुष्पेंद्र सिंह ने 56.91 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता जबकि पूनम राम ने 49.48 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। भारत 54 स्वर्ण सहित 167 पदक जीतकर शीर्ष पर बना हुआ है जबकि रूस 11 स्वर्ण से 23 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। भारत ने पुरुषों की 400 मीटर टी13 स्पर्धा में भी दबदबा बनाया जिसमें सुबोध भट्ट ने 51.88 सेकंड में स्वर्ण जीता। उनके बाद प्रियांशु कौशिक (53.19 सेकंड) और अवनिल कुमार (56.91 सेकंड) रहे।

पुरुषों की 400 मीटर टी46-टी47 स्पर्धा में भाविककुमार दीन भरवाड़ ने 49.89 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीता जबकि साथी भारतीय जसबीर 50.09 सेकंड के साथ रजत पदक जीतने में उनके ठीक पीछे रहे। सर्बिया के इवान क्वेतकोविक ने 50.93 सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। भारत ने पुरुषों की 400 मीटर टी53-टी54 स्पर्धा की व्हीलचेयर वर्ग में अपना दबदबा बनाए रखा जिसमें मनोजकुमार सबपति ने 54.33 सेकंड में स्वर्ण, अनिल कुमार ने 57.57 सेकंड में रजत और मणिकंदन जोथी ने 1:01.94 के समय के साथ कांस्य पदक जीता।

महिलाओं की स्पर्धा में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। 400 मीटर टी11-टी12 स्पर्धा में तेजलबेन अमराजी डामोर ने 57.53 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण जीता। ललिता किलाका ने 1:07.92 के समय के साथ रजत और शालिनी चौधरी ने 1:16.79 के समय के साथ कांस्य के साथ कांस्य पदक जीता। इससे भारत ने एक और पोडियम स्वीप पूरा किया।

अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स के खरीदने पर बीसीसीआई का बयान

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बीसीसीआई द हंड्रेड की नीलामी में सनराइजर्स लीड्स के पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने के मामले में दखल नहीं देगा। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बीसीसीआई का अधिकार केवल आईपीएल तक सीमित है। सनराइजर्स लीड्स ने गुरुवार को ऐसे समय पर अबरार को खरीदा जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि आईपीएल फ्रेंचाइजी की वाली द हंड्रेड की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोली नहीं लगाएंगी। लीड्स फ्रेंचाइजी का मालिकाना हक सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के पास है जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को चलाता है। राजीव शुक्ला ने एएनआई से कहा कि, हमारा डोमेन सिर्फ आईपीएल तक सीमित है। वे उसके बाहर किसी लीक में क्या करते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उनके किसी विदेशी लीग में किसी खिलाड़ी को जोड़ने में कैसे दखल दे सकते हैं। ये उन पर निर्भर है। ये पूरी तरह से उस फ्रेंचाइजी पर निर्भर करता है जिसने भारत के बाहर कोई टीम खरीदी है। अगर वे उस लीग में भारत के बाहर का कोई प्लेयर ले रहे हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि आईपीएल में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है।

पाकिस्तानी गेंदबाज को खरीदने पर घिरीं काव्या मारन सनराइजर्स लीड्स टीम का एक्स अकाउंट सस्पेंड

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। द हंड्रेड की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स की मालकिन काव्या मारन की मुश्किल बढ़ गई है। दरअसल, सनराइजर्स लीड्स का एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि द हंड्रेड की नीलामी में काव्या मारन की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद पर सबसे महंगी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया। इस फ्रेंचाइजी ने अबरार को खरीदने के लिए 2 करोड़ 34 लाख रुपये में खरीदा है।

द हंड्रेड 2026 ऑक्शन का आयोजन लंदन में हुआ। जहां काव्या मारन के साथ टीम के हेड कोच डेनियल विटोरी भी मौजूद रहे। इस नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने ट्रेंट रॉकेट्स को पछाड़ते हुए अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल करने में सफलता हासिल की। सनराइजर्स लीड्स की कप्तानी इस सीजन में इंग्लैंड के टी20 कप्तान हैरी ब्रूक के हाथों में होगी।

ऐसी घटना कई साल के बाद घटी जब किसी भारतीय फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल किया। हालांकि, काव्या मारन द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद भारत में उनकी जमकर आलोचना हो रही है और क्रिकेट फैंस आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का बॉयकॉट कर रहे हैं। वैसे सनराइजर्स लीड्स के एक्स अकाउंट को सस्पेंड क्यों किया गया इसकी सही जानकारी सामने नहीं आ पाई है।

वहीं विवाद के बाद टीम के कोच डेनियल विटोरी ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि आदिल राशिद शुरू से हमारी पसंद थे, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गए तो हमने विदेशी स्पिनर की तरफ रुख किया। चार-पांच खिलाड़ी ऐसे थे जिन पर हमारी नजर थी और अबरार उनमें से एक थे उन्हें पाकर हम खुश हैं।

विटोरी ने बताया कि मैनेजमेंट ने नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को न चुनने के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उनकी योजना सबसे अच्छी टीम चुनने की थी और जब वे आदिल राशिद को नहीं ले पाए तो उन्होंने अबरार को चुना।

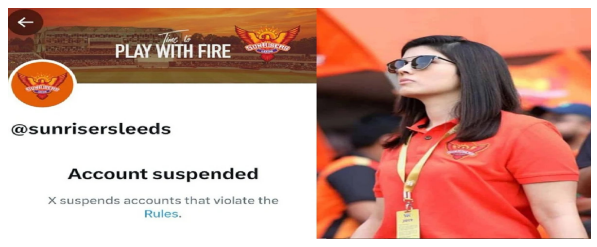

आईपीएल 2026: जोश हेजलवुड के खेलने पर अभी संस्पेंस, मेडिकल टीम की अनुमति का इंतजार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाज जोश हेजलवुड अभी भी अपने हैमस्ट्रिंग और अकिलीज टेंडन की चोट के कारण फिजियो की देखरेख में हैं। पहले उम्मीद की जा रही थी कि वह आईपीएल 2026 के लिए फिट हो जाएंगे। हालांकि, अभी रिपोर्ट के अनुसार हेजलवुड अभी भी मेडिकल टीम से अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ही आरसीबी का ये खिलाड़ी आईपीएल के 19वें सीजन के लिए उपलब्ध हो पाएगा।

मामले से जुड़े सूत्र ने हिन्दुस्तान टाइम्स के हवाले से कहा कि, वह अभी भी फिजियो की देखरेख में हैं और आईपीएल में उनकी भागदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें मेडिकल क्लियरेंस मिलती है या नहीं। अभी काफी समय है, लेकिन फिलहाल ये वेट एंड वॉच की स्थिति है। हेजलवुड का आईपीएल रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। उन्होंने 39 मैचों में 57 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका औसत 20.98 और इकॉनमी रेट 8.27 रहा है।

पिछले आईपीएल सीजन में हेजलवुड आरसीबी के स्टार गेंदबाज रहे थे। उन्होंने 12 मैचों में 22 विकेट लिए थे। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी ने रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी को पहला आईपीएल खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, नवंबर में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलते समय लगी चोट के कारण वह एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे। इसके बाद उन्हें पूरी एशेज सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर होना पड़ा था।

निशानेबाज सम्राट और सुरुचि, धावक गुलवीर और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद टॉप्स कोर समूह में शामिल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। उभरते पिस्टल निशानेबाज सम्राट राणा और सुरुचि सिंह, एशियाई स्वर्ण पदक विजेता लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह और विश्व चैंपियन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत उन आठ खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें हाल में प्रदर्शन के आकलन के बाद 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' के कोर ग्रुप में शामिल किया गया है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, बैडमिंटन स्टार एच एस प्रणय, पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता राइफल निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार और पहलवान दीपक पूनिया जैसे प्रमुख खिलाड़ियों को 'प्रदर्शन के अपेक्षित मापदंडों' को पूरा नहीं कर पाने के कारण कोर समूह से हटा दिया गया है। 'टॉप्स' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. एस. जोहल की अध्यक्षता में 'मिशन ओलंपिक सेल' (एमओसी) की 169वीं बैठक में सूची में फेरबदल किया गया। सम्राट ने जहां पिछले साल 10 मीटर एयर पिस्टल की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में विश्व चैंपियन का खिताब जीता, वहीं सुरुचि ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार चार विश्व कप स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

ओलंपिक के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता प्रमोद ने इस साल की शुरुआत में अपना छठा विश्व खिताब जीता। पोलियो के कारण बाएं पैर में विकार की दिव्यांगता का शिकार यह 37 वर्षीय खिलाड़ी लगातार तीन डोपिंग परीक्षणों में अनुपस्थित रहने के उल्लंघन के लिए 18 महीने के निलंबन के बाद पिछले साल प्रतियोगिता में लौटा है। इस सूची में शामिल होने वाले एक अन्य खिलाड़ी इस वर्ष के एशियाई रजत पदक विजेता राइफल निशानेबाज नीरज कुमार हैं। हालांकि, पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता शिव नरवाल को सूची में हुए कुछ बदलावों और नए नामों के शामिल होने के बाद 56 सदस्यीय मुख्य समूह से बाहर कर दिया गया है। पिछले साल गुलवीर के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें विकास स्तर (डेवलपमेंटल लेवल) से मुख्य स्तर पर पदोन्नत किया जाना बिल्कुल उचित था। वे 5000 मीटर और 10, 000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक भी हैं। उन्होंने पिछले साल एशियाई चैंपियनशिप में दोनों स्पर्धाओं में शीर्ष स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया था।

इसके साथ ही बैडमिंटन मिश्रित युगल जोड़ी तनीशा क्रास्टो और ध्रुव कपिला तथा पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम फेदरवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया को भी विकासात्मक स्तर से मुख्य स्तर पर पदोन्नत किया गया है। टॉप्स कोर समूह के खिलाड़ियों को 50, 000 रुपये का मासिक भत्ता मिलता है। इसके साथ ही उन्हें विदेशों में प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन 25 डॉलर भी मिलते हैं।

अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर सीबीआई का शिकंजा, 228 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी केस में हुई पूछताछ

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को 228 करोड़ रुपये के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जय अनमोल अंबानी को शनिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में उनसे पूछताछ की, जिसमें उन पर रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा पूर्व पूर्णकालिक निदेशक रवींद्र सुधाकर समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

कंपनी से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। गत 9 दिसंबर, 2025 को एजेंसी ने जय अनमोल अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद जय के आवास पर तलाशी ली गई थी। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (तत्कालीन आंध्रा बैंक) की एक शिकायत पर कार्रवाई की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया, जिससे खाता 2019 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया।

'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं', प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़ने पर दिया रिएक्शन

बॉलीवुड और साउथ से लेकर हॉलीवुड तक काम करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हमेशा चर्चा में रहती हैं। वह अपने प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी के अलावा अपने बयानों से सुर्खियों में आ जाती हैं। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया है कि वह उन लोगों में से एक नहीं हैं जो एक की जगह पर बने रहे। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि जिंदगी में सफर कभी आसान नहीं होता और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। उन्होंने बॉलीवुड से हॉलीवुड जाने पर प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने और क्या कहा है।

प्रियंका चोपड़ा ने 'नॉट स्किनी बट नॉट फैट' के साथ बात करते हुए कहा, 'मुझे गंदगी में रहना पसंद नहीं है क्योंकि फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। जब जिंदगी मुश्किल हो जाता है तो हमें ही खुद को संभालना चाहिए। दुख को महसूस करना चाहिए और फिर नई दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं जब हॉलीवुड गई तो मेरे लिए बना-बनाया रास्ता नहीं था लेकिन मुझे अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पूरा भरोसा था। मैं किसी भी फिल्ममकर या को-एक्टर के सामने खड़ी हो सकती थीं।' एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मैं जब भारत में काम कर रही थी तो मुझे लिमिटेड फील होने लगा था। मैं देखना चाहती थी कि दुनिया में और क्या संभावनाएं हैं। उस समय हॉलीवुड में पॉप कल्चर में ऐश्वर्या राय और मिंडी कलिंग जैसे बहुत कम एक्टर्स थे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं कॉम्पिटिटिव नेचर की हूं। मैं देखना चाहती थी कि वहां मेरे लिए क्या मौके हैं।'

प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने साउथ सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की थी। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द ब्लफ' में नजर आ रही हैं। ये फिल्म ओटीटी पर आई है। इस फिल्म एक्ट्रेस समुद्री डाकू के रोल में नजर आ रही हैं। वहीं, प्रियंका चोपड़ा साउथ सिनेमा के चर्चित डायरेक्टर एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी। इस फिल्म को बड़े बजट के साथ बनाया जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

15 साल का इंतजार खत्म, प्रकाश झा ने 'राजनीति' 2 पर लगाई मुहर रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल?

फिल्ममेकर, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर प्रकाश झा ने साल 2010 में एक ऐसी फिल्म बनाई दी थी, जो पर्दे पर भारतीय राजनीति के बुरे और डार्क साइड को बखूबी दिखाती थी। ये फिल्म थी 'राजनीति' जिसमें चुनावी दंगल में धन-बल, बाहुबल और छल-कपट का यूज़ दिखाया गया था। रणबीर कपूर, कैटरीना कैफ और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े-बड़े कलाकारों से सजी इस फिल्म ने उस दौरान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था, वहीं अब इसके सीक्वल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।

गौरतलब है कि, जून 2025 में प्रकाश झा ने रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर राजनीति थ्रिलर फिल्म 'राजनीति' के 15 साल पूरे होने के मौके पर इसके सीक्वल की अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा था कि, 'राजनीति का ये सफर तो अनवरत है, ये चलती ही रहती है। राजनीति 2 के लिए हमेशा से एक प्लान रहा है। हालांकि, कास्टिंग और शूटिंग के मामले में अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं अभी इसपर काम कर रहा हूं।' वहीं अब फिल्ममेकर ने इस पर ऑफिशियली मुहर लगा दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रकाश झा ने कन्फर्म करते हुए बताया कि, राजनीतिक थ्रिलर फिल्म राजनीति के सीक्वल राजनीति 2 पर वो काम कर रहे हैं। मूवी इस टाइम प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है और मैं इस पर एक्टिवली काम कर रहा हूं। उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि, पहली फिल्म की तरह इस सीक्वल में भई किरदार, घटनाएं और कहानी के कुछ हिस्से भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं से प्रेरित होंगे। उन्होंने बताया कि, 'राजनीति 2 में पौराणिक कथाओं से काफी कुछ लिया गया है।' इस खबर के सामने आने के बाद से ही फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं।

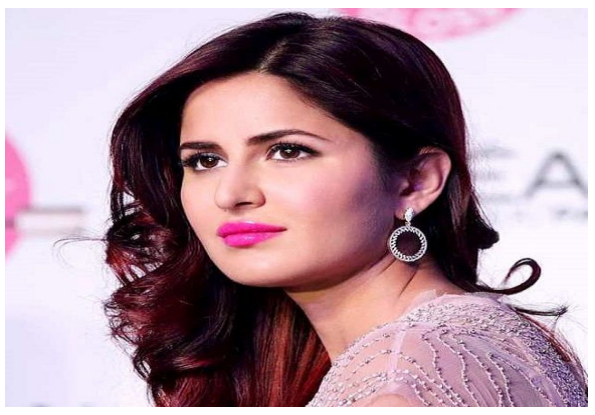

आपको बता दें कि, साल 2010 में रिलीज हुई राजनीति में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आए थे। इसके अलावा नाना पाटेकर, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी, सारा थॉम्पसन और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार भी शामिल थे। फिल्म को लेकर शुरुआत में काफी विवाद हुआ था। हालांकि, कई कंट्रोवर्सीज के बाद जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई तो लोगों ने खूब तारीफ की। 45 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने 145।50 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। हालांकि, अभी पार्ट 2 की कास्ट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

कश्मीर की सड़कों पर प्रदर्शन लौट आया! ईरान पर हमले का गुस्सा कश्मीर की सड़कों पर क्यों दिख रहा?

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में एक बार फिर वही पुराना दृश्य सामने आया है जो कभी यहां की सड़कों की पहचान बन गया था। रमजान के आखिरी जुमे के दिन श्रीनगर, मगाम और बड़गाम जैसे इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के विरोध में नारे लगाने लगे। प्रशासन को पहले से आशंका थी कि नमाज के बाद भीड़ जमा हो सकती है, इसलिए सुबह से ही कई जगहों पर पाबंदियां लगा दी गई थीं। श्रीनगर के कई हिस्सों में लोगों के जमा होने पर रोक लगाई गई और हालात पर नजर रखी गई।बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन खास तौर पर उन इलाकों में देखने को मिला जहां शिया आबादी अधिक है। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन और फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के नारे लगाए। प्रशासन का कहना है कि अब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में स्थित ऐतिहासिक जामिया मसजिद को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया।

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईरान में जो कुछ हुआ, उससे कश्मीर की सड़कों का क्या लेना देना है? अगर पश्चिम एशिया में कोई टकराव होता है तो उसका जवाब श्रीनगर और बड़गाम की गलियों में क्यों खोजा जाता है? क्या घाटी की शांति इतनी कमजोर है कि हजारों किलोमीटर दूर हुए घटनाक्रम का गुस्सा यहां की सड़कों पर उतर आता है?

कश्मीर ने पिछले कई सालों में मुश्किल दौर से निकल कर धीरे धीरे सामान्य जीवन की तरफ कदम बढ़ाए हैं। बाजार खुल रहे हैं, पर्यटन लौट रहा है और लोग हिंसा की

छाया से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर हर अंतरराष्ट्रीय घटना के नाम पर भीड़ सड़कों पर उतरने लगे तो घाटी में बनी यह शांति कब तक टिकेगी।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, वैसे ही शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन का वही पुराना पैटर्न फिर से दिखाई देने लगा। आखिर यह संयोग है या किसी संगठित सोच का हिस्सा? क्या यह महज भावनात्मक प्रतिक्रिया है या इसके पीछे वह मानसिकता है जो घाटी को बार बार सड़कों के टकराव की ओर धकेलती रही है?

यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। यहां की जनता को अपने देश की शांति और व्यवस्था की चिंता पहले करनी चाहिए। अगर हर अंतरराष्ट्रीय विवाद को लेकर यहां हंगामा खड़ा किया जाएगा तो इसका असर सीधे देश के भीतर के माहौल पर पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का समाधान श्रीनगर की सड़कों पर नारे लगाने से नहीं निकलेगा।

कश्मीर के लोगों को यह भी सोचना होगा कि दुनिया के हर संघर्ष को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेने से क्या हासिल होगा? घाटी के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य की जरूरत है, न कि हर शुक्रवार को गुस्से और नारों की राजनीति की।

प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पाबंदियां लगाकर फिलहाल स्थिति को संभाल लिया है। लेकिन असली सवाल अभी भी खड़ा है। क्या कश्मीर बार बार उसी पुराने रास्ते पर लौटेगा जहां भीड़, नारे और टकराव ही राजनीति का माध्यम बन जाते थे। अगर ईरान में कुछ हुआ है तो उस पर चर्चा विश्व मंचों पर होगी, कूटनीति के जरिये होगी और सरकारों के बीच होगी। लेकिन कश्मीर की शांति को दांव पर लगाकर आखिर कौन-सा संदेश दिया जा रहा है। घाटी को यह तय करना होगा कि उसे विकास और स्थिरता का रास्ता चुनना है या फिर दूर बैठे संघर्षों के नाम पर अपनी ही सड़कों को अशांत बनाना है।

असम चुनाव : कांग्रेस की 95 प्रतिशत सीटों पर मंथन पूरा, गोगोई बोले- कल तक आएगी लिस्ट

गुवाहाटी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक के बाद, असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने घोषणा की कि पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने 95 प्रतिशत उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने बताया कि सूची कल तक जारी होने की उम्मीद है और पार्टी शेष सीटों को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही चर्चा करेगी। गोगोई ने कहा कि हमने असम की 95 प्रतिशत सीटों पर चर्चा कर ली है। सूची कल तक जारी हो सकती है। हम जल्द ही शेष सीटों पर भी चर्चा करेंगे।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को आगामी असम विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। एक अलग घटनाक्रम में, आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सोमवार को असम में कांग्रेस को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला, जब असम गण परिषद (एजीपी) के पूर्व राष्ट्रीय वित्त सचिव जयंता खाउंद कुछ अन्य नेताओं के साथ पार्टी में शामिल हो गए।

खाउंद को पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल किया गया। इनमें असम प्रभारी और एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह अलवर, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और असम के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक डी.के. शिवकुमार, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और राष्ट्रीय सचिव मनोज चौहान शामिल थे। खाउंद का पार्टी में स्वागत करते हुए गोगोई ने कहा कि उनके जैसे जमीनी नेता का पार्टी में शामिल होना 'मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व के खिलाफ असम में बढ़ती जन असंतोष' को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि असम में राजनीतिक परिवर्तन की लहर चल रही है।

राज्यसभा चुनाव से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का डर ओडिशा कांग्रेस के 8 विधायक बेंगलुरु शिफ्ट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ओडिशा के आठ कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु ले जाया गया है और एक रिसॉर्ट में ठहराया गया है। आशंका है कि पूर्वी राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों से पहले उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विधायक गुरुवार रात अपने परिवारों के साथ पहुंचे और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की देखरेख में उन्हें बेंगलुरु दक्षिण के बिदादी स्थित वंडरला रिसॉर्ट में ले जाया गया।

एक सरकारी सूत्र ने बताया कि ओडिशा से कुल 14 लोग आए हैं और उन्हें रिसॉर्ट में ले जाया गया है। इनमें से आठ विधायक हैं और बाकी उनके परिवार के सदस्य हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री का बेंगलुरु दक्षिण जिले के बिदादी क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव माना जाता है।

ओडिशा के विधायकों को ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बेंगलुरु भेजा। स्थानीय अधिकारियों ने इनमें से पांच विधायकों की पहचान मंगू खिल्ला, पवित्र सौंता, कद्रका अप्पाला स्वामी, राजन एक्का और प्रफुल्ल प्रधान के रूप में की है।

ओडिशा की 147 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 79 विधायकों के साथ बहुमत है और उम्मीद है कि वह निर्दलीय विधायकों और क्रॉस-वोटिंग के समर्थन से राज्यसभा में तीन सदस्य भेजेगी। 48 विधायकों वाली बीजू जनता दल (बीजेडी) फिलहाल एक सदस्य भेज सकती है। हालांकि, 14 विधायकों वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, बीजेडी एक सीपीआई (एम) विधायक और तीन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से दूसरी सीट हासिल करने का लक्ष्य रख रही है।

जी7 नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- ईरान अब आत्मसमर्पण करने वाला है

वाशिंगटन। वर्चुअल बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी7 के नेताओं से कहा कि ईरान आत्मसमर्पण करने ही वाला है। यह जानकारी जी7 देशों के तीन अधिकारियों ने दी, जिन्हें इस चर्चा की जानकारी दी गई थी। प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं के साथ हुई इस कॉल के दौरान ट्रंप ने ये टिप्पणियां कीं। इस कॉल में ट्रंप ने हाल ही में हुए सैन्य अभियान 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के नतीजों के बारे में बात की। बातचीत से परिचित अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप ने इस अभियान को एक बड़ी सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। कॉल के दौरान ट्रंप ने नेताओं से कहा कि उन्होंने 'एक ऐसे कैंसर से छुटकारा पा लिया है जो हम सभी के लिए खतरा था, जिसका जिक्र उन्होंने ईरान से जुड़े हालात के संदर्भ में किया। एक्सियोस के अनुसार, सहयोगी देशों से बात करते हुए उन्होंने इस अभियान के सकारात्मक परिणामों पर भी प्रकाश डाला।

ईरान ने खाड़ी के अरब देशों पर शुक्रवार तड़के कई हमले किए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बड़े जवाबी हमले की चेतावनी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "देखते रहिए, आज इन कुटिल लोगों का क्या हश्र होता है। ईरान की नौसेना नाश हो चुकी है, वायुसेना तबाह हो गई है। मिसाइल, ड्रोन और सब कुछ खत्म हो गए हैं और उनके नेताओं का नामोनिशान धरती से मिटा दिया गया है।" उन्होंने कहा, "हम ईरान के आतंकी शासन को सैन्य, आर्थिक और हरेक तरीके से पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वे 47 वर्ष से दुनिया भर में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अब मैं, अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति होने के नाते, उन्हें मार रहा हूं। ऐसा करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है।" अमेरिकी राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों से एक दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने ईरानियों के खून का बदला लेने से पीछे न हटने का संकल्प लिया था। उन्होंने खाड़ी के अरब देशों को अमेरिकी ठिकाने बंद करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिकी सुरक्षा की धारणा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इस बीच, खाड़ी क्षेत्र के आसपास तेल और अन्य बुनियादी ढांचे पर ईरान के हमले जारी हैं। सऊदी अरब ने शुक्रवार को कहा कि उसने तड़के सुबह अलग-अलग समय भेजे गए लगभग 50 ड्रोन मार गिराए। ओमान न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ओमान के सोहार क्षेत्र के एक औद्योगिक इलाके में दो ड्रोन गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।

बहरीन में हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की आवाज सुनी गई और दुबई में एक औद्योगिक क्षेत्र से काला धुआं उठता देखा गया। अधिकारियों के अनुसार, किसी मिसाइल या हमले को रोकने की कार्रवाई (इंटरसेप्शन) के बाद गिरे मलबे से आग लग गई थी। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। अधिकारियों के अनुसार, 'सफल इंटरसेप्शन' के बाद गिरे मलबे की वजह से इमारत को नुकसान हुआ है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, देश में अब तक 1, 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल ने 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं अमेरिका के कम से कम सात सैनिकों की मौत हो चुकी है, और आठ सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास शुक्रवार तड़के तेज हवाई हमले हुए। हमलों के समय फलस्तीनियों के समर्थन में आयोजित होने वाले वार्षिक कुद्स दिवस कार्यक्रम के लिए रैलियां शुरू होने वाली थीं। इजराइल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में उसकी वायुसेना ने ईरान में 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, रक्षा प्रणालियां और हथियार उत्पादन स्थल शामिल हैं।

भारत-अमेरिका में बड़ी मिनरल डील की तैयारी अमेरिका राजदूत सर्जियो गोर ने दिया संकेत

वाशिंगटन। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कॉन्क्लेव 2026 में कहा कि दोनों देश जल्द ही एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। यह घोषणा दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के ढांचे पर सहमति बनने के कुछ दिनों बाद हुई है। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण समझौते के प्रमुख रणनीतिक पहलुओं को रेखांकित करते हुए गोर ने कहा कि हमारे देशों के बीच सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक महत्वपूर्ण खनिज हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अपरिहार्य हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमेरिका और भारत आज एक महत्वपूर्ण खनिज समझौते को अंतिम रूप देने के बहुत करीब हैं, जो उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा प्रणालियों और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से अपडेट रहने का आग्रह करते हुए कहा कि हमें इस संबंध में अगले कुछ महीनों में एक बड़ी घोषणा की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, भारत पहले से ही लगभग 300 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के उन उत्पादों का आयात कर रहा है जिनमें अमेरिका वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी है। ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, विमान, इंजन और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। मंत्री ने पिछले महीने कहा था कि भारत और अमेरिका

के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर इस महीने हस्ताक्षर होने और अप्रैल में इसके लागू होने की संभावना है। नई दिल्ली और वाशिंगटन ने एक संयुक्त बयान जारी कर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

गोर ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये संबंध राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश सरकारों, व्यापारिक समुदायों और मीडिया मंचों के माध्यम से एक-दूसरे पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा अमेरिका और भारत सरकारों, व्यापारिक समुदायों और यहां तक कि मीडिया के माध्यम से भी एक-दूसरे पर बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। और यह ध्यान एक गहरे अर्थ को दर्शाता है - एक ऐसी साझेदारी जो हर साल मजबूत, अधिक स्पष्ट और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।

गोवा की राजनीति में भाजपा का दबदबा! पणजी निगम चुनाव में मिली एकतरफा और बड़ी जीत

पणजी। नगर निगम (सीसीपी) के चुनावों के लिए मतगणना 13 मार्च (शुक्रवार) को सुबह 8:00 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में शुरू हुई। 11 मार्च को मतदान सुचारू रूप से समाप्त हो गया था। वार्ड 23 में 81.94इ मतदान के साथ 69.07इ का भारी मतदान हुआ। 30 वार्डों में 69 उम्मीदवारों ने 48 बूथों पर मतपत्रों के माध्यम से चुनाव लड़ा, जिसमें महिलाओं (10 वार्ड), ओबीसी (8) और एसटी (1) के लिए आरक्षण था। भाजपा के 'बाबुश' मोंसेरेट पैनल ने 27 सीटें जीतकर उत्पल पर्रिकर की अमी पंजेकर चुनौती को करारी शिकस्त दी।

नतीजों में बीजेपी उम्मीदवारों का दबदबा रहा शायनी चोपडेकर ने वार्ड 15 में अमी पंजेकर के सूरज रोहिदास नाइक को हराया; किशोर शास्त्री ने सुदीन कामत के खिलाफ वार्ड 5 जीता; कृष्णा

रामदास शिरोडकर वार्ड 18 बनाम आशीष रंगनाथ नागवेकर जीते; अस्मिता केरकर ने प्रांजल प्रजीत नाइक को हराकर वार्ड 16 हासिल किया; वार्ड 12 में वर्षा हरि शेट्टी ने ब्रिजेश वासुदेव कावलेकर और शबनम खान पर जीत हासिल की; प्रसाद अमोनकर ने विष्णु नाइक से वार्ड 10 पकड़ा; युतिका जाम्बौलीकर ने वार्ड 1 में रोशन मार्टिंस और दामिनी रघुवीर कुनकोलिंकर को हराया; उदय वामन मडकईकर ने वार्ड 13 पर नीलखंट चारी को हराया; निकिता नाइक ने वार्ड 19 में देओदिता वियाना परेरा पर जीत हासिल की; कबीर फिलिप पिंटो मखीजा ने सुरेंद्र व्लादिमीर एंटोनियो एंजेलो डी मोंटे फर्टाडो से वार्ड 9 पर कब्जा कर लिया; और प्रजोत संतोष वैगनकर ने वार्ड 14 बनाम मदन शंभू फतेरपेकर को हराया।

अमी पंजकर को मामूली बढ़त मिली: लियोनिद फुरतादो ने वार्ड 7 में भाजपा के संजीव देसाई को हराया और वार्ड 17 में जैक अजीत सुखीजा ने भाजपा के डेनिस एडवर्ड फ्रांसिस जॉर्ज को बेहद करीबी मुकाबले में हराया। जैक ने मात्र 2 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। भाजपा ने अपना नियंत्रण बरकरार रखा और राज्य चुनावों से पहले पणजी के शहरी एजेंडे को आकार दिया, हालांकि विपक्षी एकता ने उसकी मजबूती को चुनौती दी।

इजराइल का बड़ा एक्शन : ईरान के 200 ठिकानों पर हमला, तेहरान समेत कई शहर बने निशाना

तेल अवीव। ईरानी सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी के मुताबिक, इजरायली वायु सेना द्वारा ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की एक नई लहर के बाद पूर्वी तेहरान के रिहायशी इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ।

प्रेस टीवी पर एक पोस्ट में घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में कई घायल लोगों को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया है। यह घटना इजरायली वायु सेना द्वारा शुक्रवार को ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों की लहरों को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा के बाद घटी है।

तेहरान, शिराज और अहवाज़ में एक साथः वायु सेना ने ईरानी आतंकी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हमलों को अंजाम दिया। सैन्य खुफिया विभाग के निर्देश पर, वायु सेना ने पिछले एक दिन में तेहरान, शिराज और अहवाज़ में ईरानी आतंकी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हमलों को अंजाम दिया। दक्षिणी ईरान के शिराज में, ईरानी आतंकी शासन द्वारा इज़राइल पर दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के उत्पादन और भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक भूमिगत ठिकाने पर हमला किया गया। तेहरान मेंः ईरानी आतंकी शासन के हवाई

रक्षा तंत्र के ठिकानों और एक केंद्रीय अड्डे पर हमला किया गया। इसके अलावा, विभिन्न युद्धक साधनों, हवाई रक्षा प्रणालियों और बैलिस्टिक मिसाइलों के घटकों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई ठिकानों पर भी हमला किया गया। साथ ही, पश्चिमी ईरान के अहवाज़ में शासन के विभिन्न निकायों के मुख्यालयों पर हमला किया गया। हमला किए गए मुख्यालयों में ईरानी आतंकी शासन के सैनिकों की गतिविधि देखी गई, और दर्जनों सैनिक वहां से इज़राइल और क्षेत्र के देशों के खिलाफ आतंकी हमले करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसमें आगे कहा गया है, ये सफल हमले ईरानी आतंकी शासन की मुख्य शाखाओं और उसकी नींव को और अधिक नुकसान पहुंचाने के चरण का हिस्सा हैं।

इराक में अमेरिकी वायु सेना का केसी-135 विमान क्रैश चार अमेरिकी सैनिकों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

तेहरान। अमेरिकी वायु सेना के बोइंग केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान के पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें सवार छह चालक दल के सदस्यों में से चार की मौत हो गई है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने शुक्रवार दोपहर को एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। शेष दो चालक दल के सदस्यों को बचाने के प्रयास जारी हैं। ईरान के साथ संघर्ष से संबंधित अमेरिकी और इजरायली अभियानों का समन्वय करने वाली सैन्य कमान, सेंटकॉम ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की अभी भी जांच चल रही है। हालांकि, उसने शत्रुतापूर्ण गोलीबारी और मित्रवत गोलीबारी, दोनों को ही संभावित कारणों से खारिज कर दिया है। सेंटकॉम ने आगे कहा कि मारे गए चारों कर्मियों की पहचान 24 घंटे तक गुप्त रखी जाएगी, जब तक उनके परिवारों को सूचित नहीं कर दिया जाता।

मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों की देखरेख करने वाली अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि यह दुर्घटना 'मित्रवत हवाई क्षेत्र' में दो विमानों से जुड़ी एक अज्ञात घटना के बाद हुई। दूसरा विमान सुरक्षित उतर गया। बोइंग केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर एक लंबे समय से सेवा में रहा टैंकर विमान है जिसका उपयोग अमेरिकी वायु सेना द्वारा अन्य विमानों को हवा में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। इससे विमान लंबी दूरी तय कर सकते हैं और बिना उतरे लंबे समय तक परिचालन में रह सकते हैं। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस विमान का उपयोग चिकित्सा निकासी के दौरान घायल कर्मियों को ले जाने या निगरानी मिशन चलाने के लिए भी किया जा सकता है।

ईरान पर अमेरिका का 'अभूतपूर्व' हमला अमेरिकी युद्ध सचिव बोले- तेहरान के आसमान पर दिखेगा हमारा कंट्रोल

वाशिंगटन। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई कथित तौर पर घायल हैं और संभवतः उनका चेहरा बिगड़ गया है। यह घटना खामेनेई द्वारा अपने पिता की ईरान और अमेरिका के संयुक्त हमले में हुई मौत के बाद सत्ता संभालने के एक दिन बाद सामने आई है। हेगसेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि नए तथाकथित, लेकिन उतने सर्वोच्च नहीं माने जाने वाले नेता घायल हैं और संभवतः उनका चेहरा बिगड़ गया है। उन्होंने कल एक बयान जारी किया, लेकिन उसमें कोई आवाज या वीडियो नहीं था। यह केवल एक लिखित बयान था। ईरान के पास पर्याप्त कैमरे और वॉयस रिकॉर्डर हैं - तो फिर केवल लिखित बयान क्यों? मुझे लगता है कि आप कारण जानते हैं। वह डरे हुए हैं। वह घायल हैं। वह भाग रहे हैं, और उनकी वैधता खत्म हो चुकी है। सत्ता किसके हाथ में है, यह एक उलझन भरा मामला है। ईरान को शायद खुद भी इसका पता नहीं है।

सेक्रेटरी हेगसेथ ने ईरान में चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की सैन्य क्षमताओं को पराजित करने, नष्ट करने और निष्क्रिय करने के लिए अभूतपूर्व गति से हमले कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान अभियान लक्षित हैं और मीडिया रिपोर्टों में युद्ध के विस्तार की बात कही जाने के बावजूद अमेरिका अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है और उन पर नियंत्रण बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि आज ईरान और तेहरान के आसमान पर अमेरिका द्वारा किए जाने वाले हमलों की संख्या एक बार फिर सबसे अधिक होगी। होर्मुज जलडमरूमध्य पर, हेगसेथ ने इस दावे को खारिज कर दिया कि अमेरिकी योजनाकारों ने संघर्ष के प्रभाव को कम करके आंका था। उन्होंने कहा कि जलमार्ग आवागमन के लिए खुला है और व्यवधान केवल जहाजों पर ईरानी हमलों के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को धमकाता रहा है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित | कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 | फोन : 022-24706563 | कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com | सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 | समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)